राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण सोमवार 06 जुलाई 2026 वर्ष-9,अंक-154 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

Zentrum
Evakuierung
Bombenfund
30
FEUERWEHR
SPERRZONE
POLIZEI

लोग काम पर जाने के लिए थे तैयार, अचानक गूंजी आवाज खाली करो घर

बर्लिन।

सुबह का वक्त था और लोग रोज की तरह अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। कोई ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की ओर बढ़ रहा था तो कोई दफ्तर जाने की जल्दी में था। तभी अचानक पूरे इलाके में एक चेतावनी गूंजी। लोगों से कहा गया कि वे तुरंत अपने घर और आसपास का इलाका खाली कर दें। ये सुनते ही अफरा-तफरी मच गई और कुछ ही देर में सड़कों पर पुलिस, दमकल और राहत दलों की गाड़ियां दौड़ने लगीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना जर्मनी के पॉट्सडैम शहर की है, जहां निर्माण कार्य के दौरान जमीन के नीचे से द्वितीय विश्व युद्ध का 250 किलोग्राम वजनी जिंदा बम मिला। यह वही बम था, जो करीब 81 साल पहले युद्ध में गिराया गया था, लेकिन फटा नहीं। इतने साल बाद भी यह उतना ही खतरनाक था जितना उस दिन था, जब इसे गिराया गया था। बम मिलने के बाद प्रशासन ने कोई जोखिम नहीं लिया। करीब 6500 लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। एक वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को भी सुबह-सुबह बाहर निकालना पड़ा। इतना ही नहीं, शहर का सेंट्रल रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तर, संसद भवन, बैंक और मशहूर बारबेरीनी संग्रहालय भी सुरक्षा के लिए बंद कर दिए गए। अधिकारियों ने बम मिलने वाली जगह के चारों ओर करीब 700 मीटर का सुरक्षा घेरा बना दिया। इसके बाद बम निष्क्रिय करने वाले विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे। योजना यह थी कि बम के डेटोनेटर को हाथ से सावधानीपूर्वक खोलकर उसे अलग किया जाए, ताकि विस्फोट का खतरा खत्म हो सके। विशेषज्ञों ने बताया कि इस प्रक्रिया में करीब 30 मिनट से एक घंटे का समय लग सकता है। हालांकि उनके लिए यह रोजमर्रा के काम जैसा है, लेकिन जरा-सी चूक बड़ी तबाही मचा सकती थी।बता दें यह पहली बार नहीं था 2019 में भी पॉट्सडैम के इसी इलाके में ऐसा ही एक अमेरिकी बम मिला था, जिसके कारण करीब 5,900 लोगों को घर छोड़ना पड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुए आठ दशक से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन जर्मनी में आज भी जमीन के नीचे ऐसे हजारों जिंदा बम छिपे होने की आशंका है। माना जाता है कि युद्ध में जर्मनी पर लाखों टन बम गिराए गए थे, जिनमें से कई फटे ही नहीं।

मप्र सरकार के खिलाफ लामबंद हुए संत और पुजारी- गुना में प्रेस वार्ता कर दी खुली चेतावनी

फैसला बदलें या पुजारियों को दें सरकारी कर्मचारी का दर्जा

गुना ।

सरकार द्वारा मठ-मंदिरों की माफी जमीनों को नीलाम करने के फैसले के विरोध में गुना जिला मुख्यालय पर पुजारियों और संतों ने लामबंद होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भुजरिया तालाब स्थित प्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में मठ मंदिर पुजारी संघ जिला गुना की एक आपात और महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता महंत राघवेंद्र दास जी महाराज ने की।सरकार ने दानदाताओं की जमीनों पर जताया हक, पुजारियों को भेजे नोटिसइस दौरान आयोजित पत्रकारवार्ता में राघवेंद्र दास जी महाराज और पं. लखन शास्त्री ने पुजारियों का आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि सिर्फ गुना में लगभग 247 से अधिक मंदिरों के पुजारियों को नोटिस भेजे गए हैं। जो अलग-अलग तारीखों के हैं। वक्ताओं के अनुसार वर्तमान सरकार ने प्राचीन मठ-मंदिरों की जमीनों को नीलाम करने के उद्देश्य से पुजारियों को नोटिस जारी किए हैं, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। संतों ने स्पष्ट किया कि ये प्राचीन मंदिर और इनसे लगी जमीनें न तो सरकार की हैं और न ही सरकार ने इन्हें दान में दिया है। ये संपत्तियां प्राचीन काल में मंदिर बनवाने वाले राजाओं और दानदाताओं द्वारा भगवान के भोग, मंदिर के रखरखाव, सेवा-पूजा और पुजारियों के भरण-पोषण के लिए समर्पित की गई थीं।या तो फैसला बदलें, या पुजारियों को घोषित करें सरकारी कर्मचारीपुजारी संघ ने दोटूक शब्दों में कहा कि यदि सरकार को लगता है कि यह संपत्ति और जमीनें उसकी हैं, तो सरकार इन्हें अपने अधीन ले ले, लेकिन इसके बदले में वे मंदिरों के पुजारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करें।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी- जेल में पांच आरोपियों से पूछताछ, आरोपी अविनाश शुक्ला ने उगले राज; लेन-देन की जांच तेज

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या स्थित राम मंदिर में दान गबन मामले की जांच के लिए रविवार को विवेचक आशुतोष तिवारी एंटी करप्शन कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद जिला कारागार पहुंचे। जेल में बंद पांच आरोपियों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस कस्टडी में आरोपी अविनाश शुक्ला ने पूछताछ के दौरान करीब 19 लाख रुपये की अतिरिक्त रकम खा खुलासा किया है। अब जांच एजेंसियां इस रकम के संबंध में मिले इनपुट का सत्यापन कर रही हैं।साथ ही बरामदगी की दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ा रही हैं। सूत्रों के अनुसार, मामले में आरोपी और उनके परिजनों के बैंक खातों को भी खंगाला जा रहा है। इन खातों में हुए संदिग्ध लेन-देन का सत्यापन कराया जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि चोरी की रकम बैंकिंग सिस्टम के जरिये कहीं ट्रांसफर या खपाई तो नहीं गई।

खाड़ी से यूरोप तक भारत बदलेगा वैश्विक समीकरण

जयशंकर का वैश्विक कूटनीतिक मिशन

नई दिल्ली ।

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर रविवार से एक महत्वपूर्ण छह-देशीय कूटनीतिक यात्रा पर रवाना होंगे, जिसमें कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, बेल्जियम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। आज से 10 जुलाई तक चलने वाली उनकी चार खाड़ी देशों की यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण समय में हो रही है, जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद इस क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। यह यात्रा भारत के लिए इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का एक बड़ा अवसर है।

विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, जयशंकर अपनी खाड़ी यात्रा के दौरान इन देशों के नेताओं और अपने समकक्षों से मुलाकात करेंगे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक सशक्त बनाना है। इसके साथ ही, क्षेत्रीय घटनाक्रमों और आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श भी होगा, जिससे भारत की पश्चिम एशिया नीति को नई दिशा मिल सकती है।खाड़ी देशों का दौरा पूरा करने के बाद, विदेश मंत्री 13 जुलाई को न्यूयॉर्क के लिए प्रस्थान करेंगे, जहाँ वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में साल 2028-29 के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत करेंगे।

यह कदम वैश्विक शासन में भारत की बढ़ती आकांक्षाओं और भूमिका को दर्शाता है, जहाँ भारत स्थायी सदस्यता के लिए भी प्रयासरत है।

अपनी यात्रा के अंतिम चरण में, जयशंकर 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स जाएंगे।

यहाँ वे तीसरी भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) की बैठक में भाग लेंगे और अपने यूरोपीय संघ तथा बेल्जियम के समकक्षों के साथ महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे। टीटीसी की शुरुआत 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों में आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से की गई थी। यह परिषद भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक तकनीकी सहयोग को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे दोनों पक्षों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास और साझाकरण में लाभ मिल सके। जयशंकर का यह बहुआयामी दौरा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक कूटनीतिक पटल पर भारत की बढ़ती साख और प्रभाव को भी रेखांकित करेगा, जिससे आने वाले समय में वैश्विक समीकरणों में भारत की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है।

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक

- संसदीय कार्य मंत्री ने की घोषणा, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर होगी चर्चा

विपक्ष ने एसआईआर, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विषयों पर सरकार को घेरने की बनाई रणनीति

नई दिल्ली।

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इसकी घोषणा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने की और बताया कि भारत सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को इस अवधि के लिए बुलाने की मंजूरी दे दी है। सरकार के अनुसार, इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधायी कार्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा और बहस होगी।

मानसून सत्र के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विधेयकों, नई नीतियों और देशहित से जुड़े अहम विषयों पर संसद में विस्तृत विचार-विमर्श होने की संभावना है। सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को सदनों में पेश कर उन्हें पारित कराने की कोशिश करेगी, जबकि विपक्ष भी विभिन्न मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी में है। सत्र को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वह इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार को कई अहम मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाएगी। विपक्ष चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, चीन और अमेरिका से जुड़े व्यापारिक मुद्दों, परिसीमन, 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' के प्रस्ताव, भ्रष्टाचार के आरोपों तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज जैसे विषयों पर सरकार से जवाब मांगेगा। ऐसे में आगामी मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर तीखी बहस होने की संभावना भी बनी हुई है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सत्र न केवल सरकार के विधायी एजेंडे बल्कि विपक्ष की रणनीति और संसद में होने वाले राजनीतिक विमर्श के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

LNG आपूर्ति सामान्य- मोदी सरकार ने हटाए प्रतिबंध, होर्मुज से दौड़ेगी गैस

नई दिल्ली।

मोदी सरकार ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति पर लगाए गए आपातकालीन प्रतिबंधों को हटाया है। यह फैसला देश के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि मध्य पूर्व से भारत में आने वाली एलएनजी की आपूर्ति अब पहले की तरह सामान्य हुई है। कुछ महीने पहले होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़े तनाव के कारण गैस की आवाजाही प्रभावित हुई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार को विशेष इंतजाम करने पड़े थे। अब हालात सुधरने और जहाजों की आवाजाही सामान्य होने के बाद इन पाबंदियों की जरूरत नहीं है।

दरअसल, मार्च महीने में मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले एलएनजी जहाजों की आवाजाही में बाधा आने की आशंका बढ़ी थी। तब भारत में गैस आपूर्ति पर संभावित असर को देखकर केंद्र सरकार ने आपातकालीन नियम लागू किए थे, इसका उद्देश्य आवश्यक क्षेत्रों को गैस की प्राथमिकता से आपूर्ति सुनिश्चित करना था। वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और सामान्य आवाजाही फिर स्थापित होने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है।

इन प्रतिबंधों के हटने से उन सभी क्षेत्रों को बड़ी राहत मिलेगी जो प्राकृतिक गैस पर निर्भर हैं। इसमें सीएनजी (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) और पीएनजी (पाइप वाली प्राकृतिक गैस) उपभोक्ता, उर्वरक इकाइयां, रिफाइनरियां, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और विभिन्न औद्योगिक इकाइयां शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों को अब पहले की तरह निर्बाध गैस आपूर्ति मिल सकेगी, जिससे उत्पादन और परिचालन संबंधी चिंताएं कम होंगी। यह फैसला भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी सकारात्मक संकेत है, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होने से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।हालांकि, केंद्र सरकार ने फिलहाल रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर की कीमतों में किसी तत्काल बदलाव का ऐलान नहीं किया है। लेकिन, एलएनजी की आपूर्ति सामान्य होने से आगे चलकर पूरी सप्लाई चेन पर दबाव कम हो सकता है। यह स्थिति घरेलू और व्यावसायिक गैस के दामों पर सकारात्मक असर डाल सकती है, हालांकि कीमतों में बदलाव का अंतिम फैसला तेल कंपनियों और सरकार द्वारा अलग से लिया जाता है।

डीआर कांगो में इबोला

2- संक्रमण पर काबू पाने में कई चुनौतियां, संभावित इलाज के लिए क्लिनिकल ट्रायल शुरू

किंशासा।

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआर कांगो) में इबोला वायरस का प्रकोप लगातार गंभीर होता जा रहा है। देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार अब तक इबोला के 1,528 पुष्ट मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 492 लोगों की मौत हो गई है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य एजेंसियां लगातार निगरानी और उपचार अभियान चला रही हैं।शनिवार को जारी आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक 239 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 628 संक्रमित मरीज अस्पतालों या आइसोलेशन केंद्रों में उपचाराधीन हैं। इसके अलावा 185 संदिग्ध मामलों की भी पहचान की गई है, जिनकी जांच जारी है।स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि महामारी के 25वें और 26वें सप्ताह में संक्रमण के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। दोनों सप्ताहों में 300 से अधिक नए संक्रमित मिले, जिससे यह संकेत मिलता है कि कई क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर पर वायरस का प्रसार जारी है। रिपोर्ट में संक्रमण नियंत्रण के सामने कई बड़ी चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया है। इनमें पोस्टमार्टम के लिए नमूने लेने का स्थानीय समुदायों द्वारा विरोध, विशेष रूप से नॉर्थ किवु प्रांत के इबोला उपचार केंद्रों में सीमित क्षमता, संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का समय पर पता न चल पाना, प्रयोगशालाओं में जांच में देरी, चिकित्सा उपकरणों और संक्रमण नियंत्रण सामग्री की कमी, सुरक्षा संबंधी समस्याएं तथा कई प्रभावित इलाकों तक स्वास्थ्य टीमों की सीमित पहुंच शामिल हैं।अफ्रीका के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. मोहम्मद याकूब जनाबी ने एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पूर्वी प्रांतों इटुरी और नॉर्थ किवु में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। उन्होंने बताया कि यह अब तक बुंडिबुग्यो इबोला वायरस का सबसे बड़ा प्रकोप माना जा रहा है। डीआर कांगो में डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञ पियरे अकिलिमाली ने बताया कि जिन क्षेत्रों में संक्रमण फैला है, वहां हथियारबंद समूहों की गतिविधियां और असुरक्षा के कारण स्वास्थ्यकर्मियों को मामलों की पहचान और संपर्कों का पता लगाने में कठिनाई हो रही है। इटुरी के कई प्रभावित क्षेत्र खनन क्षेत्र हैं, जहां बाहरी लोगों की लगातार आवाजाही संक्रमण के प्रसार का जोखिम बढ़ा रही है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुंडिबुग्यो इबोला वायरस के संभावित उपचार का आकलन करने के लिए मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की घोषणा की है। फिलहाल इस वायरस के लिए कोई स्वीकृत वैक्सीन या विशेष उपचार उपलब्ध नहीं है। उधर, पड़ोसी देश युगांडा में भी इबोला के 20 पुष्ट मामले सामने आए हैं। इनमें 15 मामले सीमा पार से आए लोगों से जुड़े हैं, जबकि पांच स्थानीय संक्रमण क्वारंटाइन के दौरान सामने आए। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल समुदाय में संक्रमण फैलने के संकेत नहीं मिले हैं। संक्रमण की रोकथाम के लिए युगांडा और डीआर कांगो ने सीमा-पार संयुक्त निगरानी और स्वास्थ्य समन्वय तंत्र स्थापित किया है।

अमरनाथ यात्रा 11 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन

प्रशासन ने एडवांस रजिस्ट्रेशन और निर्धारित तिथि का पालन करने की अपील की

बालटाल।

अमरनाथ यात्रा के दूसरे दिन शनिवार को 11,399 श्रद्धालुओं ने 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं का जत्था पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे नुनवान (पहलगाम) मार्ग और 14 किलोमीटर लंबे बालटाल मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना हुआ। पुरुषों, महिलाओं और साधु-संतों ने बम-बम भोले के जयघोष के साथ अपनी धार्मिक यात्रा शुरू की। अधिकारियों के अनुसार, दोनों बेस कैंपों से सुबह हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा के सुचारू संचालन के लिए पूरे मार्ग पर बहु-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान दोनों मार्गों पर तैनात हैं और यात्रा की लगातार निगरानी कर रहे हैं।इस बीच जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए अपील की है कि वे केवल एडवांस रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही यात्रा करें और रजिस्ट्रेशन पर्ची पर अंकित निर्धारित तिथि का सख्ती से पालन करें।

अमरनाथ बाबा बर्फानी 40 दिन में 7 से घटकर 4 फीट के हुए

पहलगाम।

अमरनाथ यात्रा के दूसरे दिन पवित्र हिम शिवलिंग बाबा बर्फानी का आकार तेजी से घटता हुआ सामने आया है।

करीब 40 दिनों के भीतर बाबा बर्फानी का आकार 7 फीट से घटकर मात्र 4 फीट रह गया है, जिससे श्रद्धालु चिंतित हैं। 23 मई को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा जारी की गई पहली तस्वीर में शिवलिंग करीब 7 फीट ऊंचा था। प्रथम पूजा के दिन, 29 जून को भी हिमलिंग की ऊंचाई 5 फीट से अधिक थी। हालांकि, 3 जुलाई को सामने आई तस्वीरों में पवित्र हिमलिंग की ऊंचाई और चौड़ाई दोनों घटकर लगभग 4 फीट रह गई है। अमरनाथ यात्रा का शनिवार को दूसरा दिन है। पहले दिन 12 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। यात्रा का दूसरा जत्था आज अमरनाथ गुफा की ओर प्रस्थान करेगा, जबकि तीसरा जत्था भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हो चुका है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अमरनाथ का हिम शिवलिंग किसी तराशे हुए ब्लॉक का हिस्सा नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक आइस स्टैलेग्माइट है।

गुफा की छत से टपकते पानी के जमने से यह बनता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि गुफा के भीतर बढ़ती मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक कारणों से तापमान में वृद्धि हुई है, जिससे ऊपर से टपकने वाला पानी पहले की तरह जम नहीं पा रहा और शिवलिंग तेजी से घट रहा है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी : भारतीय जनसंघ के संस्थापक राष्ट्रवादी चिंतक

(लेखक - हर्षवर्धन पान्डे)

125 वीं जयंती पर विशेष)

डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी आधुनिक भारत के उन विराट व्यक्तित्वों में से एक थे जिन्होंने शिक्षा, कानून, राजनीति और राष्ट्रवाद के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान दिया। वे एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद्, बैरिस्टर, कुशल प्रशासक, प्रखर वक्ता और सशक्त राष्ट्रवादी नेता थे। अल्पायु में ही उन्होंने देश की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और अंततः जम्मू-कश्मीर की पूर्ण एकीकरण की लड़ाई में शहीद हो गए।

6 जुलाई 1901को कलकत्ता के अत्यन्त प्रतिष्ठित परिवार में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे जो एक प्रखर शिक्षाविद के रूप में विख्यात थे। डॉ.मुखर्जी ने 1917 में मैट्रिक किया तथा 1921 में बी0ए0 की उपाधि प्राप्त की। 1923 में लॉ की उपाधि अर्जित करने के पश्चात वह विदेश चले गये और 1926 में इंग्लैण्ड से बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौटे। अपने पिता का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी अल्पायु में ही विद्याध्ययन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएँ अर्जित कर ली थी। 1934 में मात्र 33 वर्ष की आयु में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति भी बने। इस पद पर रहते हुए उन्होंने उच्च शिक्षा के विस्तार और सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। वे एक प्रखर विचारक और लेखक भी थे। उनकी आत्मकथा लीव्स फ्रॉम ए डायरी और अन्य लेखन भारतीय इतिहास तथा शिक्षा व्यवस्था पर गहरी अंतर्दृष्टि रखते हैं। एक विचारक और शिक्षाविद के रूप में उनकी ख्याति निरन्तर आगे बढ़ती गई।

मुखर्जी की राजनीतिक यात्रा देश 1930 के दशक में शुरू हुई। वे शुरू में कांग्रेस से जुड़े लेकिन हिंदू महासभा के माध्यम से सक्रिय हुए। पत्नी सुधा देवी की 1934 में मृत्यु के बाद उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया और पूर्ण रूप से देशसेवा में लगे रहे। 1943 से 1946 तक वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। बंगाल के अकाल (1943) के दौरान उन्होंने बड़े पैमाने पर राहत कार्य संगठित किए।

डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वेच्छा से अलख जगाने के उद्देश्य से राजनीति में प्रवेश किया था। डॉ.मुखर्जी सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और सिद्धान्तवादी थे। उन्होंने बहुत से गैर कांग्रेसी हिन्दुओं की मदद से कृषक प्रजा पार्टी से मिलकर प्रगतिशील गठबन्धन का निर्माण किया। इस सरकार में वे वित्त मन्त्री बने। इसी समय वे सावरकर के राष्ट्रवाद के प्रति आकर्षित हुए और हिन्दू महासभा में सम्मिलित हुए। मुस्लिम लीग की राजनीति से बंगाल का वातावरण दूषित हो रहा था। वहाँ साम्प्रदायिक विभाजन की नौबत आ रही थी। साम्प्रदायिक लोगों को ब्रिटिश सरकार प्रोत्साहित कर रहा था। ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने यह सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया कि बंगाल के हिन्दुओं की उपेक्षा न हो। अपनी विशिष्ट रणनीति से उन्होंने बंगाल के विभाजन के मुस्लिम लीग के प्रयासों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। डॉ.मुखर्जी इस धारणा के प्रबल समर्थक थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सब एक हैं इसलिए धर्म के आधार पर वे विभाजन के कट्टर विरोधी थे। वे हिंदुत्व विचारधारा से प्रेरित जरूर थे, लेकिन सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखते थे। उन्होंने बंगाल विभाजन के समय पश्चिम बंगाल को भारत में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे मानते थे कि विभाजन सम्बन्धी उत्पन्न हुई परिस्थिति ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से थी। वे मानते थे कि आधारभूत सत्य यह है कि हम सब एक हैं। हम सभी में कोई अन्तर नहीं है। हम सब एक पर विशेष हो रक्त के हैं। एक ही भाषा, एक ही संस्कृति और हमारी विरासत भी एक है परन्तु उनके इन विचारों को अन्य राजनैतिक दल के तत्कालीन नेताओं ने अन्यथा रूप से प्रचारित-प्रसारित किया बावजूद इसके लोगों के दिलों में उनके प्रति अथाह प्यार और समर्थन बढ़ता गया।

अगस्त, 1946 में मुस्लिम लीग ने जंग की राह पकड़ ली और कलकत्ता में भयंकर बर्बरतापूर्वक अमानवीय मारकाट हुई। उस समय कांग्रेस का नेतृत्व सामूहिक रूप से राष्ट्रसेवा था। ब्रिटिश सरकार की भारत विभाजन की गुप्त योजना और षड्यन्त्र को एक कांग्रेस के नेताओं ने अखण्ड भारत सम्बन्धी अपने वादों को ताक पर रखकर स्वीकार कर लिया। उस समय डॉ. मुखर्जी ने बंगाल और पंजाब के विभाजन की बड़ी माँग उठाकर प्रस्तावित पाकिस्तान का विभाजन कराया और आधा बंगाल और आधा पंजाब खण्डित भारत के लिए बचा लिया। गांधी और सरदार पटेल के अनुरोध पर वे भारत के पहले मन्त्रिमण्डल में शामिल हुए जहां उन्हें उद्योग और आपूर्ति मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्र भारत की औद्योगिक नीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने देश के आर्थिक विकास की नींव रखी। हालांकि, पाकिस्तान के प्रति नेहरू की तुष्टिकरण नीति से असहमत होकर उन्होंने 1950 में अपना इस्तीफा देने में भी देरी नहीं की। संविधान सभा और प्रान्तीय संसद के सदस्य और केन्द्रीय मंत्री के नाते उन्होंने शीघ्र ही अपना विशिष्ट स्थान बना लिया किन्तु उनके राष्ट्रवादी चिन्तन के चलते अन्य नेताओं से मतभेद बराबर बने रहे। राष्ट्रीय हितों को प्रतिबद्धता को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानने के कारण उन्होंने मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया जिसके बाद उन्होंने एक नई पार्टी बनाई जो उस समय विरोधी पक्ष के रूप में सबसे बड़ा दल था।

उनका सबसे बड़ा योगदान 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना करना था, जिसके वे संस्थापक अध्यक्ष भी बने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहायता से गठित यह पार्टी बाद में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती बनी। जनसंघ का उद्देश्य सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म भारत और मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा पर आधारित वैकल्पिक राजनीति प्रस्तुत करना था और 1952 के आम चुनावों में पार्टी ने तीन सीटें भी जीती। डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग भी बनाना चाहते थे। उस समय जम्मू कश्मीर का अलग झंडा और अलग संविधान था। वहाँ का मुख्यमंत्री वजीरे आलम अर्थात प्रधानमन्त्री कहलाता था। संसद में अपने भाषण में मुखर्जी ने धारा-370 को समाप्त करने की भी जोरदार वकालत की। डॉ. मुखर्जी भारत की अखंडता के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने अनुच्छेद 370 का घोर विरोध किया जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। उनका प्रसिद्ध नारा था 卐एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे।卐

अगस्त 1952 में जम्मू की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया था कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊँगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। उन्होंने तत्कालीन नेहरू सरकार को चुनौती दी तथा अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहे। अपनी मजबूत संकल्प शक्ति से 1953 में वे कश्मीर घाटी में प्रवेश करने के लिए सत्याग्रह पर उतरे। जम्मू-कश्मीर सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया। तभी जेल में उनकी तबीयत बिगड़ी और 23 जून 1953 को मात्र 51 वर्ष की आयु में उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उनका बलिदान कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत में समाहित करने के संकल्प का एक बड़ा प्रतीक बन गया। डॉ. मुखर्जी का जीवन संदेश देता है कि सच्चा राष्ट्रवाद केवल शब्दों में नहीं, बल्कि बलिदान में प्रकट होता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं)

ब्रिटिश सरकार की भारत विभाजन की गुप्त योजना और षड्यन्त्र को एक कांग्रेस के नेताओं ने अखण्ड भारत सम्बन्धी अपने वादों को ताक पर रखकर स्वीकार कर लिया। उस समय डॉ. मुखर्जी ने बंगाल और पंजाब के विभाजन की बड़ी माँग उठाकर प्रस्तावित पाकिस्तान का विभाजन कराया और आधा बंगाल और आधा पंजाब खण्डित भारत के लिए बचा लिया। गांधी और सरदार पटेल के अनुरोध पर वे भारत के पहले मन्त्रिमण्डल में शामिल हुए जहां उन्हें उद्योग और आपूर्ति मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई।

संपादकीय

घटिया निर्माण

इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता कि जिस दिल्ली-देहरादून इकोनमिक कारिडोर का उद्घाटन इसी अप्रैल में प्रधानमंत्री ने किया था, उसकी सड़क पहली बरसात में ही धंस गई। यह सड़क इतनी बुरी तरह धंसी कि कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। यह गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन यह प्रश्न तो उठेगा ही कि आखिर कोई नई बनी सड़क ढाई माह में ही पहली बरसात का सामना क्यों नहीं कर पाई? इस प्रश्न का संभावित उत्तर यही हो सकता है कि या तो सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया या फिर जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई। कारण कुछ भी हो, इस तरह के मामले सड़क निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी की ही कहानी कहते हैं। यह कोई पहला मामला नहीं, जब कोई नई बनी सड़क धंस गई हो। इस तरह की घटनाएं रह-रहकर सामने आती रहती हैं। कभी नई बनी सड़क धंस जाती है तो कभी नया बना पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है। कुछ मामले तो ऐसे भी सामने आए हैं कि कोई पुल उद्घाटन के पहले ही गिर गया। समस्या केवल यही नहीं कि सड़कों और पुलों के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता। समस्या यह भी है कि कई बार उनकी डिजाइन में तमाम खामियां होती हैं, जिसके चलते दुर्घटनाएं होती हैं। यह ठीक है कि दिल्ली-देहरादून इकोनमिक कारिडोर की सड़क धंसने के मामले को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने गंभीरता से लिया और संबंधित प्रोजेक्ट मैनेजर एवं टीम लीडर को निलंबित करने के साथ कारिडोर का रखरखाव करने वाली कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन यदि इस मामले में कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाती तो आगे भी ऐसे शर्मनाक मामले देखने को मिलेंगे। यह ध्यान रहे कि निलंबन या स्थानांतरण कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती। ज्यादातर मामलों में निलंबित अधिकारी कुछ समय बाद या तो बहाल हो जाते हैं या फिर उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि घटिया निर्माण के लिए जिम्मेदार कंपनियां यदि कभी काली सूची में डाली भी जाती हैं तो कुछ समय बाद वे इस सूची से बाहर आ जाती हैं या फिर नाम बदलकर नए सिरे से सक्रिय हो जाती हैं। यदि सड़कों, पुलों और बुनियादी ढांचे संबंधी अन्य निर्माण की गुणवत्ता में अनदेखी के सिलसिले को रोकना है तो संबंधित अधिकारियों को कठोर दंड का भागीदार बनाना होगा। अपने देश की समस्या यह है कि घटिया निर्माण या फिर सार्वजनिक सुरक्षा उपायों की अनदेखी के चलते होने वाले बड़े से बड़े हादसों के दोषी किसी अधिकारी की नौकरी मुश्किल से ही जाती है, क्योंकि जांच नौकरशाह करते हैं और वे येन-केन-प्रकारेण अपने साथी नौकरशाहों का बचाव ही करते हैं। इसका ही नतीजा है कि घटिया निर्माण का सिलसिला थम नहीं रहा है।

ज्यादातर मामलों में निलंबित अधिकारी कुछ समय बाद या तो बहाल हो जाते हैं या फिर उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि घटिया निर्माण के लिए जिम्मेदार कंपनियां यदि कभी काली सूची में डाली भी जाती हैं तो कुछ समय बाद वे इस सूची से बाहर आ जाती हैं या फिर नाम बदलकर नए सिरे से सक्रिय हो जाती हैं।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन और बलिदान से देश को दिए प्राण

(लेखक-हेमेन्द्र क्षीरसागर)

(06 जुलाई, डां श्यामाप्रसाद मुखर्जी जयंती विशेष)

डां श्यामाप्रसाद मुखर्जी ऐसे महान देशभक्त थे जिन्होंने राष्ट्र के चरमोत्कर्ष, एकता और अखण्डता की यज्ञवेदी पर अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया। वह एक साथ ही शि क्षाविद्, लेखक, सासंद, राजनीतिज्ञ और मानवतावादी कट्टर देशभक्त थे। इन्होंने विद्याध्ययन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की और शीघ्र ही एक प्रख्यात शि क्षाविद् और प्रशासक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। उनकी इस उपलब्धि को मान्यता उस समय प्राप्त हुई जब 1934 में कलकत्ता विश्विद्यालय के कुलपति नियुक्त होने वालों में वह सबसे कम आयु के थे। डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के निर्माताओं में से थे।

राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रबल समर्थक डां श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था। वे उन नेताओं में से थे, जो खुद आगे आकर जोखिम झेलते हैं। उनके लिए भारत प्रथम था और भारत की अखण्डता और वैभव ही प्रमुख लक्ष्य। जान दे दी, पर कश्मीर जाने नहीं दिया। मंत्रीमंडल को ठोकर मार दी, लेकिन सिंद्धातों से समझौता नहीं किया। हॉ, मैं हिन्दू हूँ इस देश का राष्ट्रत्व हिन्दू हैं। यह अटल सत्य हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि हिन्दू किसी दूसरे मजहब या उपासना पद्धति के विरूद्ध हैं। ऐसा होता तो इतिहास ही कुछ और होता। कश्मीर हर हिन्दुस्तानी का हैं। हर दिल में कश्मीर के लिए दर्द उठना चाहिए जो हनीफुद्दीन और अजय आहूजा के दिलों में उठा।

डॉ. मुखर्जी ने अपने जीवन और अपने बलिदान, दोनों से ही इस देश को प्राण दिए। उनके लिए भारतीय होने का अर्थ राजनीति के कपट जाल में फॅसना नहीं, वरन् उस कपट जाल को तोडना था। बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि आज जो पंजाब और बंगाल का हिस्सा भारत में दिखता हैं, उसके पीछे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखजी का जुझारूपन और आंदोलन मुख्य कारण रहे हैं। डॉ. मुखर्जी के वह शब्द इतिहास में प्रसिद्ध हैं, जब उन्होंने कहा था, 'कांग्रेस ने हिन्दुस्तान का बॅटवारा किया और मैंने पाकिस्तान का।' इस देश का दुर्भाग्य रहा कि स्वतंत्र, किन्तु खंडित भारत की कमान उस व्यक्ति के हाथों में सौंपी गई, जिसे भारतीयता किवां हिन्दुत्व से चिढ थी और स्वयं को देश का अंतिम ब्रिटिश शासक कहलाने में गर्व का अनुभव करता था।

श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने देखा कि विभाजन की भीषण त्रासदी झेलकर जो हिन्दु भारत पहॅुच रहे हैं और जो पाकिस्तान में रह गए हैं, उनके प्रति पंडित नेहरू बेहद उपेक्षपूर्ण और बहुत हदतक निर्मम नीति अपना रहे हैं। इस बिन्दु पर सरदार पटेल और पं. नेहरू में गम्भीर मतभेद पैदा हो गए थे। सरदार पटेल तो यहॉ तक चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान से कुछ जमीन ले लेनी चाहिए। भले ही इसके लिए सशस्त्र पुलिस कार्यवाही ही क्यों न करनी पडे पं. नेहरू ने लियाकत अली से समझौताकर हिन्दुओं के भविष्य को पूरी तरह पाकिस्तानी दरिन्दों के हाथों में छोड दिया। यह देखकर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आगबबूला हो उठे और उन्होंने उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया।

अपना त्यागपत्र देते समय उन्होंने इसके पीछे के कारणों का विस्तार से उल्लेख किया जो आज भी ऐतिहासिक तथा प्रेरणप्रद एक दस्तावेज के रूप में माना जाता हैं।

संकल्पित, मंत्रीमण्डल से त्यागपत्र देने के बाद डॉ. मुखर्जी ने संसद में प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने का निश्चय किया। लेकिन वह जल्दी ही समझ गए कि प्रतिपक्ष की प्रभावी भूमिका निभाने के लिए संगठित पार्टी बनाना जरूरी हैं। इसी उद्देश्य से वह प्रतिपक्ष के राजनीतिक मंच के गठन की संभावनाओं को तलाशने की ओर अग्रसर हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी किसी सशक्त व्यक्तित्व के नेतृत्व में राजनीतिक दल प्रारंभ किए जाने की जरूरत महसूस कर रहा था। डॉ. मुखर्जी और स्वयंसेवक संघ दोनों ही जिस बात की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे। वह समान थी और इसी में से अक्टूबर, 1951 में भारतीय जनसंघ का उद्भव हुआ जिसके संस्थापक अध्यक्ष डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे।

डॉ. मुखर्जी को अपने जीवन में बडी चुनौती का समना दो वर्ष बाद 1953 में करना पडा। जम्मू और कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की पृथकतावादी राजनीतिक गतिविधियों से उभरी अलगाववादी प्रवृत्यिां 1952 तक बल पकडने लगी थीं, जिससे राष्ट्रीय मानस विक्षुब्ध हो उठा। डॉ. मुखर्जी ने प्रजा परिषद् के सत्याग्रह को पूर्ण दिया जिसका उद्देष्य जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना था। उस समय जम्मू कश्मीर का अलग झण्डा था, अलग संविधान था और वहां का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाता था।

डॉ. मुखर्जी ने जोरदार नारा बुलन्द किया थाः '' एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो विधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अगस्त 1952 में जम्मू की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त कियाः या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा।'' अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने नई दिल्ली में नेहरू सरकार और श्रीनगर में शेख अब्दुला की सरकार को चुनौती देने का निश्चय किया और पं. नेहरू से कहा कि वे जम्मू जरूर जाएंगे और बिना 'परमिट' के जाएंगे।

बलिवेदी, 11 मई को रावी पर करते समय ही लखनपुर में डॉ. मुखर्जी को गिरफ्तार कर श्रीनगर जेल ले जाया गया। 40 दिन तक न उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई और न अन्य बुनियादी सुविधाएं दी गई। भारत का यह शेर श्रीनगर की जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में 23 जून 1953 को चिरनिद्रा में सोया गया। श्रद्धांजलि स्वरूप नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35 ए द्वारा दिए गए विशेष दर्जे को हटाने के लिए संसद ने 5 अगस्त, 2019 को मंजूरी दी। यह ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाला ऐतिहासिक कदम था।

सुखी जीवन की राह

एक राजा हमेशा तनाव में रहता था। एक दिन उससे मिलने एक विचारक आया। उसने राजा से उसकी परेशानी पूछी तो वह बोला - मैं एक सफलतम राजा बनना चाहता हूं, जिसे प्रजा का हर व्यक्ति पसंद करे। मैंने अब तक अनेक सफल राजाओं के विषय में पढ़ा और उनकी नीतियों का अनुसरण किया, किंतु मुझे वैसी सफलता नहीं मिली। लाख प्रयासों के बावजूद मैं एक अच्छा राजा नहीं बन पा रहा हूं।

राजा की बात सुनकर विचारक ने कहा- जब भी कोई व्यक्ति अपनी प्रकृति के विपरीत कोई काम करता है, तो यही होता है। राजा ने हैरानी जताते हुए कहा - मैंने अपनी प्रकृति के विपरीत क्या काम किया?

विचारक बोला - तुम्हें बाकी लोगों पर हुक्म चलाने का अधिकार प्रकृति से नहीं मिला है। तुम जब बाकी लोगों की तरह साधारण जीवन बिताओगे, तभी तुम्हें आनंद मिलेगा। जंगल में रहने वाले शेर की जान उसकी खाल की वजह से हमेशा खतरे में रहती है, क्योंकि वह बहुत कीमती होती है।

इसी वजह से वह रात में शिकार पर निकलता है, इस भय से कि सुंदर खाल के कारण उसे कोई मार न डाले। शेर तो अपनी खाल को नहीं त्याग सकता, किंतु तुम अपनी सफलता के लिए स्वयं को राजा मानना छोड़ सकते हो। जब तक स्वयं को राजा मानते रहोगे, दुख ही पाओगे।

राजा को विचारक की बात जंच गई और उस दिन से वह सुखी हो गया।

दरअसल अपेक्षा दुख का कारण है। इसलिए किसी से कोई अपेक्षा न रखें और अपने कर्म करते हुए सहज जीवन जिएं तो निर्मल आनंद की अनुभूति सुलभ हो जाती है।

विचार मंथन

घरों का सोना बाहर निकलवाने की तैयारी में सरकार

(लेखक -सनत जैन)

भारत सरकार इन दिनों बड़े आर्थिक संकट में फंसी हुई है। भारत सरकार के ऊपर देसी और विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार 26 जून 2026 को 5.654 अरब डॉलर घटकर 666.933 अरब डालर रह गया है। रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह गोल्ड रिजर्व में भी गिरावट दर्ज की है। डॉलर एवं अन्य विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपए की स्थिति कमजोर बनी हुई है। ऐसी स्थिति में राजकोषीय घाटे और वैश्विक भुगतान की स्थिति को संभालना सरकार के लिए कठिन होता जा रहा है। इस संकट से निपटने के लिए सरकार की निगाह भारत के लोगों के पास जो सोना जमा है, उस पर टिकी है और उसको बाहर निकलवाने के लिए योजना बनाई जा रही है। वैश्विक आर्थिक संस्थानों के अनुमान के अनुसार भारत में लोगों के पास 24000 से लेकर 30000 टन सोना जमा होने का अनुमान है। इतना सोना विश्व के 10 विकसित राष्ट्रों के सेंट्रल बैंक में भी नहीं है। भारत सोने का सबसे बड़ा आयातक देश है। ऐसी स्थिति में सरकार लोगों के घरों में जमा सोने को सरकारी सिस्टम से जोड़ने के लिए योजना तैयार कर रही है। सरकार का मानना है, भारत के घरों में जो सोना जमा है। उसे ज्वैलर्स के माध्यम से बाहर निकलवाया जाए।

नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का ऐलान सरकार मानसून सत्र में कर सकती है। इस योजना के तहत लोगों को सोना जमा करने पर ज्वेलर्स अथवा बैंक के पास जमा सोने पर ब्याज देने और जरूरत पड़ने पर तत्काल कर्ज सुविधा से जोड़कर, सरकार सोने के भंडार को सरकारी सिस्टम में लाना चाहती है। इसके लिए सरकार कई महीनो से हर स्तर पर चर्चा कर रही है। जिस तरह की आर्थिक स्थिति भारत की बनी है उसको देखते हुए सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर लोगों के घरों का सोना निकालकर उसे अर्थव्यवस्था मे लाने का प्रयास कर रही है।

सरकार का यह प्रयास सफल हो गया, तो सरकार को बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से विकास योजनाओं के लिए बड़ी धनराशि प्राप्त हो सकती है। पहले जो स्कीम सामने आई थी, उसमें केवल बैंक में ही सोना जमा करने की अनुमति थी। अब सरकार जो नई स्कीम लाने जा रही है, उसमें बैंक के अलावा ज्वेलर्स के यहां पर भी लोग सोना जमा कर सकेंगे। सोने पर जमाकर्ता को ब्याज भी मिलेगा। भारत में जो सोना स्त्री धन के रूप में घरों में है। उस पर अभी लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता है। बैंक में एफडी के रूप में जमा रकम पर जिस तरह से लोगों को ब्याज मिलता है, सरकार चाहती है, उसी तरह लोगों को सोना जमा करने पर न्यूनतम ब्याज भी हासिल हो। समय के साथ सोने में मूल्य वृद्धि का लाभ भी लोगों को मिले। इसके लिए जल्द ही सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है, इस योजना में देशभर के सर्राफा कारोबारियों को भी शामिल किये जाने की योजना है। सरकार का मानना है लोगों का अपने ज्वेलर्स के ऊपर विश्वास होता है। इस स्कीम के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सोना लाने में सर्राफा कारोबारियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। सरकार सराफा कारोबारियों को भी इंसेंटिव देने पर विचार कर रही है।

सरकारी सूत्रों का कहना है, सरकार बाजार से इस वर्ष 1000 टन से ज्यादा सोना एकत्रित करने की योजना बना रही है। जल्द ही इस योजना का खुलासा सरकार करने जा रही है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने कहा है, भारत के ज्वेलर्स सरकार की इस योजना में भाग लेने के लिए सहमत हैं। कई दौर की बातचीत, वित्त मंत्रालय और बैंकों के बीच हो चुकी है।

संभावना व्यक्त की जा रही है, इसी मानसून सत्र में नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की घोषणा सरकार कर सकती है। भारत में जिस तेजी के साथ आयात बढ़ रहा है। उस मुकाबले निर्यात नहीं बढ़ पा रहा है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध ने भारत सरकार का ऊर्जा खर्च तेजी के साथ बढ़ाया है, जिसके कारण सरकार को विदेशी मुद्रा भुगतान में कठिनाई हो रही है। सरकार इस कठिनाई से जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहती है। इसके लिए अब एक मात्र सहारा नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है, सरकार की जो नीतियां हैं, उसके कारण यह स्थिति बनी है।

सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। नीतियों में बदलाव नहीं किया गया, तो इसका बहुत ज्यादा फायदा होने की संभावना नहीं है। सरकार को आर्थिक नीतियों की समीक्षा करने के लिए अच्छे आर्थिक विशेषज्ञों की जरूरत है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और राजनेता इस समस्या का समाधान निकालने में सक्षम नहीं है। सरकार पिछले 12 वर्षों से यही गलती कर रही है। जिसका खामियाजा अब सरकार को भी भुगतना पड़ रहा है।

गैस संकट से थमी रायबरेली रेल पहिया कारखाने की रफ्तार

गैस आपूर्ति ठप होने से मात्र 7300 पहिए ही बन सके, वार्षिक लक्ष्य 60,000 का

रायबरेली ।

भारतीय ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। ईरान-इजराइल युद्ध के कारण बाधित हुई गैस आपूर्ति ने देश के रेल पहिया उत्पादन कारखाने की कमर तोड़ दी है। गैस की कमी के चलते पिछले तीन माह में कारखाना केवल 7300 पहिए ही बना पाया है, जबकि चालू वित्त वर्ष का लक्ष्य 60,000 पहियों का है। यह गंभीर संकट ईरान-इजराइल युद्ध के कारण गैस आपूर्ति में आई रुकावट से पैदा हुआ है, क्योंकि कारखाने को आवश्यक मात्रा में गैस नहीं मिल पा रही है। प्रति वर्ष 80 हजार से एक लाख रेल पहिए बनाने की क्षमता वाले इस कारखाने का उत्पादन पहले आरआईएनएल के तहत धीमा रहा था। अप्रैल 2024 में भारतीय रेलवे ने इसका अधिग्रहण किया और आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना (आरेडिका) के अधिकारियों-कर्मचारियों की मेहनत से उत्पादन में सुधार देखा गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 22562 और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 33515 पहियों का

उत्पादन हुआ था। हालांकि, मौजूदा गैस संकट ने इस प्रगति पर विराम लगा दिया है ।और रेलवे के लिए अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करना अब एक बड़ी चुनौती बन गया है।

पायरेसी पर केंद्र का कड़ा प्रहार- टेलीग्राम को सख्त नोटिस, 15 दिन में मांगी रिपोर्ट

- प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करने पर जोर, आपराधिक श्रेणी में आएगा पायरेटेड कंटेंट साझा करना

नई दिल्ली। फिल्म और ओटीटी कंटेंट की चोरी (पायरेसी) पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाते हुए मशहूर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को सख्त नोटिस जारी किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से शेयर हो रही पायरेटेड सामग्री पर तत्काल रोक लगाने को कहा है और अगले 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब छोटे-मोटे लिंक्स या चैनल्स को ब्लॉक करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि प्लेटफॉर्म को अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। मंत्रालय ने कड़े शब्दों में याद दिलाया है कि भारत में पायरेसी सिर्फ एक दीवानी उल्लंघन नहीं, बल्कि कॉपीराइट एक्ट, 1957 और सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952 के तहत एक गंभीर आपराधिक श्रेणी का अपराध है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल शिकायत मिलने पर चैनल्स हटाना आईटी एक्ट, 2000 और आईटी रूल्स, 2021 के तहत प्लेटफॉर्म की पूरी जिम्मेदारी (ड्यू डिलिजेंस) को साबित नहीं करता।

क्यूब हाईवेज ट्रस्ट 5000 करोड़ रुपए के आईपीओ की तैयारी में

निवेशक आधार बढ़ाने पर जोर, 27 राजमार्ग परिसंपत्तियों का है ट्रस्ट का पोर्टफोलियो

नई दिल्ली ।

राजमार्ग अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) क्यूब हाईवेज ट्रस्ट इस महीने 5,000 करोड़ रुपये का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की योजना बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक, यह पूरा निर्गम बिक्री पेशकश (ओएफएस) के रूप में होगा, जिसमें मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे और ट्रस्ट कोई नई पूंजी नहीं जुटाएगा। ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य सूचीबद्ध होने के बाद अपने निवेशक आधार का विस्तार करना और यूनिट में कारोबार को बढ़ाना है। मार्च 2026 तक, क्यूब हाईवेज ट्रस्ट के पास देश के 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में कुल 8,754 लेन किलोमीटर की 27 परिचालन वाली राजमार्ग परिसंपत्तियां हैं, जिनकी औसत शेष रियायती अवधि 18 वर्ष है। ट्रस्ट के पोर्टफोलियो का लगभग 85 फीसदी हिस्सा टोल सड़क परियोजनाओं का है, जिन्हें यातायात वृद्धि और महंगाई से जुड़ी टोल दरों में संशोधन का लाभ मिलता है। शेष 15 फीसदी परिसंपत्तियां एन्यूटी आधारित परियोजनाएं हैं, जिनसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की अनुबंधित भुगतान व्यवस्था के तहत स्थिर आय प्राप्त होती है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ट्रस्ट ने प्रति यूनिट 13.77 रुपये के वितरण की घोषणा की थी। इस अवधि में नौ अधिग्रहण पूरे होने से ट्रस्ट की प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां (एयूएम) बढ़कर 36,842 करोड़ रुपये पर पहुंच गईं। ट्रस्ट ने लगभग 7,300 करोड़ रुपये के संयुक्त उपक्रम मूल्य वाली चार नई राजमार्ग परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्धता पत्र भी हासिल किए हैं, जिससे पोर्टफोलियो बढ़कर 31 परिसंपत्तियों का हो जाएगा। प्रायोजकों से तीन अतिरिक्त परिसंपत्तियों पर 'राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर' भी मिला है, जो भविष्य के विस्तार की संभावनाओं को मजबूत करता है।

बिहार आईटी हब बनने को तैयार बेंगलुरु मीट में वैश्विक दिग्गजों ने दिखाई निवेश में दिलचस्पी

मंत्री नीतीश मिश्रा और सचिव अभय कुमार सिंह ने वैश्विक कंपनियों को किया आकर्षित

मुंबई ।

बेंगलुरु में आयोजित बिहार आईटी इंडस्ट्री मीट 2026 में बिहार सरकार को देश और दुनिया की अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली है। राज्य को देश के अग्रणी डिजिटल और प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से हुई इस बैठक में निवेशकों ने बिहार की नई नीतियों और कुशल मानव संसाधन में गहरी रुचि दिखाई। इस सफल आयोजन ने बिहार में बड़े पैमाने पर डिजिटल निवेश और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त किया है। बिहार सरकार का सूचना प्रावैधिकी विभाग राज्य को डिजिटल क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए सक्रिय है। इसी कड़ी में बेंगलुरु में बिहार आईटी इंडस्ट्री मीट 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें देश-विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) लीडर्स, स्टार्टअप्स और उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बिहार में निवेश आकर्षित करना और वैश्विक तकनीकी कंपनियों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करना था। इस अवसर पर बिहार सरकार के सूचना प्रावैधिकी मंत्री श्री नीतीश मिश्रा ने राज्य के आधुनिक तकनीकी इकोसिस्टम को विकसित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि बिहार आईटी पॉलिसी 2024 और बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2026 बड़े निवेश, रोजगार सृजन और राज्य को वैश्विक तकनीकी मानचित्र पर नई पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित होंगी।

कोल इंडिया और यूपीआरवीयूएनएल के बीच हुआ समझौता

साझेदारी से सौर, पवन और पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं पर होगा काम

नई दिल्ली ।

उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा क्रांति को नई गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल हुई है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) ने राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु एक संयुक्त उपक्रम (जेवी) समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य प्रदेश की बढ़ती बिजली जरूरतों को टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल समाधानों से पूरा करना है। लखनऊ में हुए इस समझौते के तहत एक नई जेवी कंपनी का गठन होगा, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड की 51 फीसदी और यूपीआरवीयूएनएल की 49 फीसदी हिस्सेदारी होगी।

नौ महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक की नीलामी रद्द, निवेशकों की अरुचि बनी चुनौती

- सरकार की आयात निर्भरता घटाने की योजना प्रभावित

नई दिल्ली।

केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में एक बार फिर झटका लगा है। निवेशकों की उदासीन प्रतिक्रिया और पर्याप्त बोलीदाताओं की कमी के चलते सरकार ने नौ महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज ब्लॉक की नीलामी रद्द कर दी है। यह फैसला देश की ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भरता घटाने की रणनीतिक योजनाओं के लिए एक बड़ा धक्का माना जा रहा है। खान मंत्रालय के अनुसार, सातवें दौर की नीलामी में शामिल किए गए कुल 19 ब्लॉकों में से दो के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई- इनमें मध्य प्रदेश का मझौली टाइटेनियम, वैनेडियम एवं एल्युमिनस लैटराइट ब्लॉक तथा राजस्थान का रैमब देगाना टंगस्टन, लिथियम एवं संबद्ध खनिज ब्लॉक शामिल हैं। वहीं, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में स्थित सात अन्य ब्लॉकों (मुख्यतः ग्लॉकोनाइट, वैनेडियम और ग्रेफाइट) के लिए तकनीकी रूप से तीन से कम पात्र बोलीदाता मिले, जिसके कारण उनकी नीलामी निरस्त कर दी गई। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि तकनीकी जटिलताओं, अधिक पूंजीगत लागत और नियामकीय अनिश्चितताओं के चलते निजी निवेशकों को ऐसे खनिज ब्लॉकों की ओर आकर्षित करना अब भी एक बड़ी चुनौती है। सरकार इससे पहले भी महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की कई नीलामियां रद्द कर चुकी है, जो इस क्षेत्र में लगातार आ रही समस्याओं को रेखांकित करता है। सातवें दौर में पहली बार गुजरात, उत्तराखंड और तेलंगाना के ब्लॉक शामिल किए गए थे, जिससे देश में महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण का दायरा विस्तृत हुआ था।

शीर्ष 10 में से 6 कंपनियों के मूल्यांकन में 1 लाख करोड़ का इजाफा

भारती एयरटेल और बजाज फाइनेंस ने मारी बाजी

नई दिल्ली ।

पिछले सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली, जिसके परिणामस्वरूप देश की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से छह का संयुक्त बाजार मूल्यांकन एक लाख करोड़ रुपये से अधिक बढ़ गया। इस उछाल में भारती एयरटेल और बजाज फाइनेंस ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। सकारात्मक घरेलू आर्थिक संकेतकों और वैश्विक मौद्रिक नीति में नरमी की उम्मीदों ने निवेशकों के विश्वास को मजबूत किया, जिससे बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों में भी उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की गई। पिछले सप्ताह बीएसई का बेंचमार्क सेंसेक्स 663.44 अंक (0.86 प्रतिशत) और एनएसई का निफ्टी 214.85 अंक (0.89 प्रतिशत) बढ़कर बंद हुआ। बाजार के जानकारों ने बताया कि घरेलू मैक्रोइकॉनोमिक संकेतकों में मजबूती, जीएसटी संग्रह में अच्छी वृद्धि और औद्योगिक गतिविधि में सुधार ने बाजार को गति दी। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका के श्रम बाजार के उम्मीद से नरम आंकड़ों के बाद अधिक उदार वैश्विक मौद्रिक नीति की उम्मीदों ने निवेशकों का भरोसा और बढ़ाया। इस दौरान भारती एयरटेल का बाजार मूल्यांकन 36,529.21 करोड़ रुपये बढ़कर 11,63,877.30 करोड़ रुपये हो गया, जो शीर्ष 10 में सबसे बड़ी बढ़त रही। बजाज फाइनेंस ने 33,059.83 करोड़ रुपये की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की, जिससे इसका मूल्यांकन 6,43,141.36 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। आईसीआईसीआई बैंक

(16,084.29 करोड़ रुपये), एचडीएफसी बैंक (7,664.89 करोड़ रुपये), भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) (8,601.99 करोड़ रुपये) और हिंदुस्तान यूनिलीवर (6,461.38 करोड़ रुपये) भी फायदे में रहे। हालांकि, कुछ कंपनियों के बाजार मूल्यांकन में गिरावट भी आई। रिलायंस इंडस्ट्रीज को 18,945.56 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जबकि लार्सन एंड टुब्रो (26,572.2 करोड़ रुपये) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) (4,846.08 करोड़ रुपये) के मूल्यांकन में भी कमी दर्ज की गई।

इन उतार-चढ़ाव के बावजूद, रिलायंस इंडस्ट्रीज 17,64,981.36 करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण के साथ देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो, एलआईसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्थान आता है।

वैश्विक संकेतों और कंप नियों के नतीजों पर टिकी बाजार की नजर

अमेरिका-ईरान वार्ता कच्चे तेल के उतार-चढ़ाव और टीसीएस के तिमाही परिणाम तय करेंगे शेयर बाजार की दिशा

मुंबई ।

घरेलू शेयर बाजारों में बीते सप्ताह रही तेजी के बाद निवेशकों की नजर अब इस सप्ताह में वैश्विक और घरेलू कारकों पर टिक गई है।

अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, और प्रमुख आईटी कंपनी टीसीएस के पहली तिमाही के नतीजे बाजार की चाल निर्धारित करेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार, आगामी सप्ताह में वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाक्रम बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम शांति समझौते को लेकर जारी वार्ता पर निवेशकों की पैनी नजर बनी रहेगी।

इस वार्ता का परिणाम न केवल वैश्विक स्थिरता को प्रभावित करेगा, बल्कि कच्चे तेल की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव ला सकता है। कच्चे तेल की कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संवेदनशील हैं, क्योंकि इनकी तेजी आयात बिल बढ़ाती है और रुपये पर दबाव डालती है, जबकि नरमी राहत प्रदान कर सकती है। इसके अतिरिक्त, विदेशी शेयर बाजारों के रुझान और विदेशी संस्थागत निवेशकों की गतिविधियां भी भारतीय बाजार को प्रभावित करेंगी।

घरेलू स्तर पर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), देश की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी, के पहली तिमाही के नतीजे 09 जुलाई को घोषित होंगे। ये नतीजे केवल टीसीएस के प्रदर्शन को ही नहीं दर्शाएंगे, बल्कि पूरे आईटी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक होंगे। विश्लेषकों का मानना है कि टीसीएस की आय, मुनाफा और विशेष रूप से प्रबंधन की भविष्य की टिप्पणी अन्य तकनीकी शेयरों की दिशा और बाजार के समग्र मूड को प्रभावित कर सकती है। निवेशकों को कंपनी की विकास संभावनाओं और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच उसके लचीलेपन पर ध्यान देना होगा।

इस हफ्ते दो कंपनियों से निवेशकों को मिलेंगे बोनस शेयर

गोल्डियाम इंटरनेशनल और हिंदुस्तान इंसुलेटर्स ने एक्स-डेट व रिकॉर्ड डेट 10 जुलाई तय की

नई दिल्ली ।

भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दो कंपनियां गोल्डियाम इंटरनेशनल लिमिटेड और हिंदुस्तान इंसुलेटर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा देने जा रही हैं। इस कॉर्पोरेट एक्शन के लिए एक्स-डेट और रिकॉर्ड डेट 10 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है, जिससे निवेशकों को भविष्य में बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार गोल्डियाम इंटरनेशनल लिमिटेड (सिक्योरिटी कोड- 526729, गो ल्डियम) ने अपने निवेशकों के लिए 1-3 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने का फैसला किया है। इसका अर्थ है कि कंपनी के हर 3 मौजूदा शेयरों पर निवेशकों को 1 अतिरिक्त शेयर मुफ्त मिलेगा, जिससे उनके शेयरों की कुल संख्या में वृद्धि होगी। इसी कड़ी में, हिंदुस्तान इंसुलेटर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सिक्योरिटी कोड- 539984,` हिल) भी अपने शेयरधारकों पर मेहरबान हुई है। इस कंपनी ने 2-1 के धमाकेदार अनुपात में बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। यानी, प्रत्येक 1 शेयर पर आपको 2 नए बोनस शेयर मिलेंगे, जिससे आपका कुल शेयर होल्डिंग तीन गुना हो जाएगा। दोनों ही कंपनियों ने इस बोनस तोहफे के लिए एक्स-डेट और रिकॉर्ड डेट 10 जुलाई तय की है।

वैश्विक बाजार में सोने की जोरदार वापसी, साप्ताहिक बढ़त से निवेशकों में उत्साह

अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड तेजी के साथ 4200 डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंच गया

नई दिल्ली ।

कई सप्ताह की नरमी के बाद वैश्विक सोने के बाजार में इस हफ्ते जोरदार तेजी दर्ज की गई है। मई के बाद पहली बार सोने ने साप्ताहिक आधार पर मजबूत बढ़त हासिल की, जिससे निवेशकों में उत्साह का माहौल है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड 2.2 प्रतिशत की तेजी के साथ 4200 डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंच गया। इस उछाल की मुख्य वजह अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीदों का कमजोर होना है। जून के रोजगार आंकड़ों के बाद फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में बढ़ोतरी की संभावना कम हुई है, जिससे डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट आई। इसके साथ ही, दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों की बढ़ती खरीदारी ने भी सोने को बड़ा सहारा दिया। भारतीय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर भी इसका असर दिखा। यहां गोल्ड फ्यूचर्स 1.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,47,365 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि सिल्वर फ्यूचर्स 2.11 प्रतिशत चढ़कर 2,34,081 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियां बनी रहती हैं, तो सोने में आगे भी मजबूती आ सकती है। अमेरिकी निवेश बैंक जेपी मॉर्गन ने चौथी तिमाही में सोने के 4,500 डॉलर

प्रति औंस तक पहुंचने का अनुमान जताया है। उनका मानना है कि केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी और सुरक्षित निवेश की मांग लंबी अवधि में सोने को समर्थन देती रहेगी।

निफ्टी ने अनिश्चितता छोड़ी पीछे, 24,500 के ऊपर नई रफ्तार संभव

बैंकिंग सेक्टर मजबूत, भागीदारी का दायरा बढ़ा।

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार एक ऐसे नए दौर में है, जहां सूचकांकों के बजाय सेक्टरों की बदलती ताकत अगली तेजी का आधार बनेगी। निफ्टी ने मजबूती दिखाते हुए संकेत दिया कि खरीदार बाजार पर पकड़ बना रहे हैं, जिससे अनिश्चितता पीछे छूटी है। निफ्टी के लिए 24,490-24,510 का क्षेत्र सबसे बड़ी बाधा है, जिसे पार करने पर 24,630 से 24,860 तक की नई तेजी मिल सकती है। 24,060-24,080 निकट अवधि का महत्वपूर्ण समर्थन रहेगा, जबकि 23,800 मजबूत आधार का काम कर सकता है। विकल्प आंकड़ों में 24,500 पर कॉल ओपन इंटरेस्ट प्रतिरोध और 24,000 पर पुट ओपन इंटरेस्ट आधार दर्शाता है। लगभग 1 का पीसीआर ऊपर बढ़ने की संभावना

को इंगित करता है। इस पूरे बाजार में बैंकिंग सेक्टर सर्वाधिक मजबूत रहा है और अगली बड़ी चाल से पहले स्वस्थ कंसोलिडेशन में है। 58,740-58,760 के ऊपर बंद होने पर बैंक निफ्टी 59,600 से 60,000 की ओर बढ़ सकता है। निजी बैंक मजबूत हो रहे हैं, जबकि पीएसयू बैंकों में स्वस्थ मुनाफावसूली है।

तेल-तिलहन बाजार में मिला-जुला रुख, मूंगफली-बिनौला मजबूत, सरसों-सोयाबीन कमजोर

सस्ता होने से मूंगफली और उपलब्धता की कमी से बिनौला तेल में उछाल

नई दिल्ली ।

बीते सप्ताह देश के तेल-तिलहन बाजारों में कीमतों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। सूरजमुखी तेल के महंगा होने और बिनौला तेल की कम उपलब्धता के कारण उपभोक्ताओं की मांग मूंगफली और बिनौला तेल की ओर बढ़ी, जिससे इनके दाम में सुधार आया। वहीं, ऊंची कीमतों पर कमजोर खरीदारी, प्लांट वालों की ओर से दाम घटाने और लागत से नीचे बिक्री के दबाव में सरसों, सोयाबीन और पाम तेलों के दाम में गिरावट दर्ज की गई। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, सूरजमुखी तेल की बढ़ी हुई कीमतें और बिनौला तेल की बेहद कम उपलब्धता ने मूंगफली तेल की मांग को बढ़ाया। सस्ता विकल्प होने के कारण मूंगफली तेल की औद्योगिक और खुदरा मांग तेज हुई, जिससे इसके दाम में सुधार आया। इसी तरह, नमकीन बनाने वाली कंपनियों से बिनौला तेल की औद्योगिक मांग बनी रहने और उपलब्धता न के बराबर होने के चलते इसके दाम भी सुधरे। दूसरी ओर, ऊंची कीमतों के कारण सरसों तेल की खरीदारी धीमी रही, क्योंकि उपभोक्ता सस्ते आयातित तेलों को तरजीह दे रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप बीते सप्ताह सरसों तेल-तिलहन में गिरावट दर्ज की गई। सोयाबीन तेल-तिलहन में भी प्लांट मालिकों द्वारा खरीद के दाम घटाने के कारण कमजोरी दिखी। सूत्रों ने बताया कि लागत मूल्य से नीचे बिकवाली के दबाव के चलते कच्चे पामतेल (सीपीओ) और पामोलीन के दाम भी लुढ़क गए, जिससे इन तेलों के भाव गिरावट के साथ बंद हुए।

सूत्रों ने बताया कि बीते सप्ताह सरसों दाना 50 रुपये की गिरावट के साथ 7,525-7,550 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों तेल 50 रुपये की गिरावट के साथ 15,525 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों पक्की और कच्ची घानी तेल क्रमश- 10-10 रुपये की गिरावट के साथ क्रमश- 2,565-2,665 रुपये और 2,565-2,710 रुपये टिन (15 किलो) पर बंद हुआ। समीक्षाधीन सप्ताह में सोयाबीन दाना और सोयाबीन लूज का थोक भाव क्रमश- 100-100 रुपये की गिरावट के साथ क्रमश- 7,000-7,050 रुपये और 6,850-6,925 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। इसी प्रकार दिल्ली में सोयाबीन तेल 75 रुपये की गिरावट के साथ 15,400 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन इंदौर तेल 175 रुपये की गिरावट के साथ 15,250 रुपये और सोयाबीन डीगम तेल 25 रुपये की गिरावट के साथ 11,975 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ।

पश्चिम एशिया में शांति बहाली के बाद भारत ने प्राकृतिक गैस आपूर्ति पर आपात प्रतिबंध हटाए

पेट्रोलियम मंत्रालय ने होर्मुज जलडमरूमध्य से एलएनजी आपूर्ति सामान्य होने के बाद अधिसूचना जारी की

नई दिल्ली ।

पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव कम होने और होर्मुज जलडमरूमध्य से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति सामान्य होने के बाद केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस आपूर्ति पर लगाए गए अधिकांश आपातकालीन प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 में किए गए उन संशोधनों को हटा दिया, जो घरेलू और आयातित गैस की आपूर्ति को सरकार द्वारा तय प्राथमिकता सूची के अनुसार विनियमित करते थे। सरकार ने ये आपातकालीन प्रतिबंध नौ मार्च को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लागू किए थे, जब पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने और अमेरिका-इजरायल की ओर से ईरान पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य से एलएनजी की आवाजाही प्रभावित हुई थी। उस समय कई अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं ने फोर्स मेज्योर लागू कर दिया था, जिससे भारत सहित कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर गहरा असर पड़ने की आशंका पैदा हो गई थी। मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि अब क्षेत्र में युद्धविराम लागू है, राजनयिक बातचीत जारी है और होर्मुज जलडमरूमध्य से समुद्री यातायात पूरी तरह से सामान्य हो चुका है। ऐसे में गैस आपूर्ति पर लगाए गए इन आपातकालीन प्रावधानों को जारी रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है। पश्चिम एशिया संकट के दौरान, सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुल तीन बड़े कदम उठाए थे। इनमें प्राकृतिक गैस आपूर्ति का नियंत्रण, रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश और थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल की बिक्री को सीमित करना शामिल था। एलपीजी उत्पादन और डीजल बिक्री से जुड़े प्रतिबंध पहले ही वापस ले लिए जा चुके थे, और अब गैस आपूर्ति से जुड़े प्रावधान भी समाप्त कर दिए गए हैं। भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 88 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस की लगभग आधी आवश्यकता आयात के जरिये पूरी करता है। इसमें से लगभग 40-45 प्रतिशत कच्चा तेल और 65 प्रतिशत एलएनजी आयात पश्चिम एशिया से होता है। यही कारण है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी तरह का व्यवधान भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती माना जाता है।

विंबलडन में बदल रही है चैंपियनों की किस्मत! स्वियातेक बाहर, दिमित्रोव-कीज ने बचाई उम्मीदें

लंदन, एजेंसी। विंबलडन 2026 में लगातार ऐसे नतीजे सामने आ रहे हैं, जिन्होंने टेनिस प्रशंसकों को चौंका दिया है। महिला एकल में जहां मौजूदा चैंपियन इगा स्वियातेक का सफर तीसरे दौर में ही खत्म हो गया, वहीं अनुभवी खिलाड़ियों ग्रिगोर दिमित्रोव और मैडिसन कीज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथे दौर में जगह बना ली। बड़े उलटफेर और रोमांचक मुकाबलों ने इस बार के विंबलडन को और दिलचस्प बना दिया है।

एलेक्जेंड्रा एला ने रचा इतिहास, स्वियातेक को किया बाहर

21 वर्षीय फिलीपींस की एलेक्जेंड्रा एला ने टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए मौजूदा चैंपियन और तीसरी वरीयता प्राप्त इगा स्वियातेक को 7-6(9), 6-2 से हराया। पहले सेट के टाईब्रेक में दो सेट प्वाइंट बचाने के बाद एला ने पूरे मैच पर अपना नियंत्रण बना लिया। इस जीत के साथ वह ग्रैंड स्लैम के दूसरे सप्ताह में पहुंचने वाली फिलीपींस की पहली खिलाड़ी बन गईं। पिछले कुछ महीनों से शानदार फॉर्म में चल रही एला ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह बड़े खिलाड़ियों को चुनौती देने का दम रखती हैं। अब उनका सामना 13वीं वरीयता प्राप्त जैस्मीन पाओलिनी से होगा।

दिमित्रोव की दमदार वापसी, पांच सेट तक चला रोमांच

पुरुष एकल में बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव ने इटली के माटेओ बेरेटिनी को 6-3, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3 से हराकर चौथे दौर में जगह बनाई। तीन घंटे 32 मिनट तक चले मुकाबले में दिमित्रोव ने शुरुआती दो सेट आसानी से जीत लिए थे, लेकिन बेरेटिनी ने शानदार वापसी कर मैच को निर्णायक सेट तक पहुंचा दिया।निर्णायक सेट में दिमित्रोव ने अनुभव का शानदार प्रदर्शन किया और महत्वपूर्ण समय पर सर्विस ब्रेक हासिल कर जीत दर्ज की। मैच के बाद उन्होंने कहा, 'पिछले साल की निराशा के बाद इस कोर्ट पर जीत हासिल करना मेरे लिए बेहद खास है। यह सिर्फ जीत या हार की बात नहीं है, बल्कि हर चुनौती को पार करने के बारे में है।' अब चौथे दौर में उनका सामना ब्रिटेन के वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी आर्थर फेरी से होगा।

कीज ने दिखाई चैंपियन जैसी वापसी

महिला एकल में अमेरिका की 26वीं वरीयता प्राप्त मैडिसन कीज ने पहला सेट गंवाने के बावजूद अमांडा अनिसिमोवा को 3-6, 6-2, 6-3 से हराकर अंतिम-16 में जगह बनाई। कीज की यह लगातार 10वीं ग्रास कोर्ट जीत रही और वह करियर में छठी बार विंबलडन के चौथे दौर में पहुंची हैं।अनिसिमोवा ने पहले सेट में शानदार शुरुआत की थी, लेकिन दूसरे और तीसरे सेट में सात डबल फॉल्ट उनकी हार की बड़ी वजह बने। दूसरी ओर कीज ने अपने दमदार बेसलाइन शॉट्स और सटीक सर्विस के दम पर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। अब उनका सामना चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा से होगा।

खिताब की दौड़ हुई और रोमांचक

स्वियातेक और दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना के बाहर होने से महिला वर्ग पूरी तरह खुल गया है। वहीं दिमित्रोव और कीज जैसे अनुभवी खिलाड़ियों ने यह संकेत दे दिया है कि इस बार विंबलडन में अनुभव और धैर्य भी खिताब की दौड़ में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। चौथे दौर के मुकाबलों के साथ टूर्नामेंट अब और रोमांचक होने की उम्मीद है।

ईशान बोले-हमने परफेक्ट टीम चुनी थी

दूसरे टी-20 मुकाबले में हार के बाद ईशान किशन ने टीम चयन पर उठ रहे सवालों का दिया जवाब

लंदन(एजेंसी)। मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में हार के बाद ईशान किशन ने टीम चयन पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। ऑफ स्पिनर की कमी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि टीम प्रबंधन ने सर्वश्रेष्ठ संयोजन के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया था।ईशान ने कहा, 'नहीं, मेरा मानना है कि हमने परफेक्ट टीम चुनी थी। जब आप मैच नहीं जीतते हैं तो बहुत सारे सवाल और अगर-मगर सामने आने लगते हैं। लेकिन हमारे सभी गेंदबाज बेहतरीन हैं। उन्होंने पहले भी अलग-अलग परिस्थितियों में टीम को जीत दिलाई है। सपाट विकेटों पर भी विकेट निकाले हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि टीम चयन के लिहाज से हम कुछ अलग कर सकते थे।'

विदेशी परिस्थितियों को बेहतर समझना होगा

हालांकि ईशान ने माना कि भारतीय टीम को इंग्लैंड की परिस्थितियों के अनुसार खुद को बेहतर ढंग से ढालने की जरूरत है। उन्होंने कहा, 'हमें यह समझना होगा कि परिस्थितियां कैसी हैं और हम उनमें कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हम भारत के बाहर खेल रहे हैं, इसलिए बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को यह समझना होगा कि यहां की पिच हमसे क्या मांगती है। सिर्फ एक बल्लेबाज या एक गेंदबाज अंतर नहीं ला सकता। पूरी टीम को मिलकर यह समझना होगा कि हम कहां सुधार कर सकते हैं।'

हमें 20 रन और जोड़ने होंगे

ईशान किशन का मानना है कि भारत लगातार अपनी पारियों के आखिरी ओवरों में गति खो रहा है, जिससे टीम 15-20 रन पीछे रह जा रही है। उन्होंने कहा, 'हमें यह देखना होगा कि हम अतिरिक्त 20 रन कहां से बना सकते हैं। चाहे चौके-छक्कों से या बड़े मैदानों में गैप्स का बेहतर इस्तेमाल करके। इंग्लैंड के बल्लेबाज यहां की परिस्थितियों को हमसे बेहतर समझते हैं।

इंग्लैंड ने बनाई सीरीज में बढ़त

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन (49), अभिषेक शर्मा (43) और कप्तान श्रेयस अय्यर (37) की पारियों की मदद से 190/7 का स्कोर बनाया। जवाब में इंग्लैंड ने जैकब बेथेल की नाबाद 76 रन की शानदार पारी के दम पर 19 ओवर में 191/6 बनाकर मुकाबला चार विकेट से जीत लिया। भारत की हार में 17वां ओवर निर्णायक साबित हुआ, जिसमें रवि बिश्नोई ने 29 रन खर्च किए।

सह-मेजबान कनाडा का सफर समाप्त

- लगातार दूसरी बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में मोरक्को

ह्यूस्टन। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ-16 मुकाबले में मोरक्को ने सह-मेजबान कनाडा को 3-0 से हराकर लगातार दूसरी बार क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार मिडफील्डर अज़्ज़ेदीन औनाही ने दूसरे हाफ में दो गोल दागे, जबकि इंजरी टाइम में सुफियान रहीमी ने तीसरा गोल कर जीत पर मुहर लगा दी। अब मोरक्को का सामना 9 जुलाई को बोस्टन में होने वाले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस और पराग्वे के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता टीम से होगा।

पहले हाफ में कनाडा का दबदबा, लेकिन गोल नहीं

मुकाबले की शुरुआत में कनाडा ने शानदार खेल दिखाया और लगातार आक्रमण करते हुए मोरक्को की रक्षा पंक्ति पर दबाव बनाया। मैच का पहला बड़ा मौका कनाडा को मिला, जब अली अहमद के पास पर तानी ओलुवासेयी गोलकीपर के सामने पहुंच गए। हालांकि, मोरक्को के कनाडा में जन्मे गोलकीपर यासीन बूनू ने शानदार बचाव कर अपनी टीम को शुरुआती झटका लगने से बचा लिया। पहले हाफ में मोरक्को को उस समय बड़ा झटका लगा, जब टूर्नामेंट के उनके शीर्ष स्कोरर इस्माइल साइबारी मांसपेशियों में चोट के कारण 22वें मिनट में मैदान छोड़ने पर मजबूर हो गए। उनकी जगह सुफियान रहीमी को उतारा गया।

दूसरे हाफ में औनाही का जलवा

ब्रेक के बाद मोरक्को ने पूरी तरह मैच का रुख बदल दिया। 50वें मिनट में अशरफ हाकिमी के शानदार सेट-पीस पास पर अज़्ज़ेदीन औनाही ने बॉक्स के बाहर से बेहतरीन पहली टाइमिंग वाला शॉट लगाकर गेंद को नेट में पहुंचा दिया और मोरक्को को 1-0 की बढ़त दिलाई। इस गोल के बाद मोरक्को का आत्मविश्वास बढ़ गया, जबकि कनाडा की टीम दबाव में आ गई। 82वें मिनट में तेज जवाबी हमले के दौरान ब्राहिम डियाज के पास पर औनाही ने अपना दूसरा गोल दागते हुए स्कोर 2-0 कर दिया।

रहीमी ने जीत पर लगाई मुहर

इंजरी टाइम (90+8वें मिनट) में ब्राहिम डियाज के शानदार थ्रू पास पर सुफियान रहीमी ने गोल दागकर मोरक्को की 3-0 की शानदार जीत सुनिश्चित कर दी। रहीमी इससे पहले एक हेडर में क्रॉसबार से भी टकराए थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपना नाम स्कोरशीट में दर्ज करा ही लिया।

मोरक्को ने रचा इतिहास

इस जीत के साथ मोरक्को लगातार दूसरी बार फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। इसके साथ ही वह विश्व कप इतिहास में एक से अधिक बार अंतिम-8 में पहुंचने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया। कतर 2022 में सेमीफाइनल तक पहुंचकर इतिहास रचने वाली एटलस लायंस की टीम ने एक बार फिर खिताब की दौड़ में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। वहीं, कनाडा का शानदार विश्व कप अभियान राउंड ऑफ-16 में समाप्त हो गया। हालांकि, इस टूर्नामेंट में टीम ने पहली बार विश्व कप में मैच जीतने के साथ नॉकआउट चरण तक पहुंचकर अपने देश के फुटबॉल इतिहास में नया अध्याय जरूर जोड़ा।

फ्रांस-पराग्वे के खिलाड़ी भिड़े, हुई धक्का-मुक्की

फ्रांस और पराग्वे के बीच राउंड ऑफ-16 मुकाबले की आखिरी सीटी बजते ही मैदान पर माहौल गर्म हो गया। दोनों टीमों के खिलाड़ी आमने-सामने आ गए और कुछ देर तक धक्का-मुक्की भी देखने को मिली। मैच के दौरान ही फ्रांस के कप्तान किलियन एमबाप्पे और पराग्वे के गोलकीपर ऑरलैंडो गिल के बीच भी तनातनी हो गई। एमबाप्पे ने गिल से हाथ नहीं मिलाया, जिसके बाद नाराज गोलकीपर ने उनके जाते समय पीठ पर मैच बॉल फेंक दी। हालांकि, फ्रांसीसी स्टार ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और अपनी टीम के साथ जीत का जश्न मनाते रहे। मैच में दोनों टीमों के बीच 70 मिनट तक कड़ी टक्कर देखने को मिली। मैच के दौरान कई ऐसे पल आए, जब दोनों टीमों के खिलाड़ी भिड़ने पर आ गए। पर एक वक्त एमबाप्पे की लड़ाई पराग्वे के डिएगो गोमेज से हो गई। इसके बाद पराग्वे के खिलाड़ी एमबाप्पे को धक्का देने लगे। इस पर फ्रांस के खिलाड़ी भी पहुंच गए और जमकर धक्का मुक्की हुई। रेफरी पहले तो बीचबचाव करते हुए एमबाप्पे को साइड ले जाते दिखे, फिर जब दोनों टीमों के खिलाड़ी आ गए तो रेफरी ने किनारा कर लिया।

खत्म हो गई मुरली विजय और दिनेश कार्तिक के बीच दुश्मनी

चेन्नई, एजेंसी। एक समय भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित विवाद का हिस्सा रहे मुरली विजय और दिनेश कार्तिक अब शायद पुराने मतभेदों को पीछे छोड़ चुके हैं। तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे मुरली विजय ने अपने संबोधन के दौरान दिनेश कार्तिक को लेकर ऐसी बातें कहीं, जिसने क्रिकेट प्रशंसकों को हैरान कर दिया। वर्षों तक एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने वाले विजय ने सार्वजनिक मंच से कार्तिक की तारीफ करते हुए उन्हें अपना बेहद अजीज दोस्त बताया।

मंच से दिनेश कार्तिक की जमकर तारीफ

अपने भाषण में मुरली विजय ने कहा कि वह बचपन से दिनेश कार्तिक को खेलते हुए देख रहे हैं और उनके खेल के हमेशा प्रशंसक रहे हैं। उन्होंने कहा, 'अब मुझे दिनेश कार्तिक के बारे में बात करनी है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मैं उन्हें बचपन से देखता आया हूं। वह तमिलनाडु के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं। वह एक बेहद गतिशील व्यक्तित्व के मालिक और मेरे बेहद अजीज दोस्त हैं।'

विजय ने आगे कहा, 'मैंने नॉन-स्ट्राइकर एंड से कई बार उनकी बल्लेबाजी को करीब से देखा है। उनके जैसा खेलते हुए मैंने किसी और को नहीं देखा। वह शानदार क्रिकेटर हैं। उनके अनुभव और क्रिकेट की समझ ने मेरे करियर में काफी मदद की है और इसके लिए मैं मंच से उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं।'

क्या था दोनों के बीच विवाद?

मुरली विजय और दिनेश कार्तिक के बीच का विवाद 2010 के शुरुआती वर्षों में सामने आया था। उस समय दोनों तमिलनाडु और भारतीय टीम के लिए साथ खेलते थे और बेहद करीबी दोस्त माने जाते थे। बाद में दिनेश कार्तिक और उनकी तत्कालीन पत्नी निकिता वंजारा का रिश्ता टूट गया। इसके बाद निकिता ने मुरली विजय से शादी कर ली। इस घटना के बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच दूरियां बढ़ गईं। हालांकि, दोनों ने कभी भी सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं की।

शानदार वापसी की

निजी जीवन में बड़े झटके के बावजूद दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट में शानदार वापसी की। उन्होंने खुद को भारत के भरोसेमंद फिनिशर के रूप में स्थापित किया और कई यादगार पारियां खेलीं। बाद में उन्होंने भारतीय स्क्वैश स्टार दीपिका पल्लीकल से शादी की। हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वह आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा हैं और क्रिकेट कमेंट्री व विश्लेषण में भी सक्रिय हैं। मुरली विजय के इस भावुक बयान को सोशल मीडिया पर काफी सराहा जा रहा है।

संजू सैमसन के समर्थन में उतरे अंबाती रायुडू

लंदन। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को अंतरराष्ट्रीय डेब्यू का मौका मिला, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया। इस फैसले के बाद भारत के पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायुडू ने संजू के समर्थन में सोशल मीडिया पर भावुक संदेश साझा किया। रायुडू ने कहा कि सूर्यवंशी का डेब्यू जश्न मनाने लायक है, लेकिन संजू सैमसन के हालिया योगदान को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

रायुडू ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, 'आइए संजू सैमसन के बारे में भी एक पल सोचें। वैभव को डेब्यू करते देखना बेहद खुशी की बात है और इसका जश्न मनाया जाना चाहिए, लेकिन यह मत भूलिए कि सिर्फ तीन टी20 मैच पहले संजू टी20 विश्व कप में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' थे। मुझे उम्मीद है कि वह दमदार वापसी करेंगे। साथ ही मैं वैभव सूर्यवंशी के लंबे और रिकॉर्ड तोड़ने वाले करियर की भी शुभकामनाएं देता हूं।'संजू सैमसन पहले टी20 मुकाबले में सिर्फ सात गेंदों पर एक रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद टीम प्रबंधन ने बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करते हुए युवा वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया।

प्रज्ञानंद ब्लिट्स में पिछड़े, अलीरेजा ने बढ़त बनाई

जागरेब(एजेंसी)। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ग्रैंड चेस टूर के क्रोएशिया चरण में रैपिड वर्ग वाला अपना शानदार फॉर्म दोहराने में नाकाम रहे और ब्लिट्ज वर्ग के शुरुआती नौ दौर में सिर्फ 3.5 अंक ही हासिल कर पाए। इस बीच फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा ने शानदार खेल दिखाते हुए एकल बढ़त बना ली है। प्रतियोगिता में अब सिर्फ एक दिन का खेल बाकी है।

प्रज्ञानंद चौथे स्थान पर खिसके

अलीरेजा ने तेज खेल वाले प्रारूप में कमाल का खेल दिखाया और नौ में से आठ अंक हासिल किए। उन्होंने 20 अंक के साथ अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वियों उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव और फ्रांस के मैक्सिम वाचियेर लाग्रेव पर तीन अंक की बड़ी बढ़त बना ली है। प्रज्ञानंद 15.5 अंक के साथ चौथे स्थान पर खिसक गए, जबकि विश्व चैंपियन डी गुकेश का दिन भी औसत रहा और वे 14 अंक के साथ पांचवें स्थान पर हैं। ग्रैंड चेस टूर के इतिहास में सबसे दमदार प्रदर्शन में से एक में अलीरेजा ने आधे खिलाड़ियों को कम से कम सात अंक पीछे छोड़ दिया है। जर्मनी के विन्सेंट कीमर 13 अंक के साथ छठे स्थान पर हैं। नीदरलैंड के अनीश गिरी उनसे आधा अंक पीछे हैं, जबकि रोमानिया के डीक बोगदान डैनियल के 11.5 अंक हैं। नीदरलैंड के जोर्डन वैन फोरेस्ट उनसे दो अंक और पीछे हैं, जबकि क्रोएशिया के इवान सारिक सिर्फ पांच अंक के साथ सबसे नीचे हैं।

ब्लिट्ज वर्ग में नौ दौर का खेल शेष

रैपिड वर्ग के बाद अलीरेजा के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर चल रहे प्रज्ञानंद ब्लिट्ज वर्ग में अपनी लय खो बैठे। दिन की शुरुआत कीमर पर जीत के साथ करने के बाद प्रज्ञानंद ने गिरी के साथ अगली बाजी ड्रॉ खेली लेकिन फिर लगातार चार हार ने उनके आत्मविश्वास को कम कर दिया। टूर्नामेंट के चौथे दिन भारतीय खिलाड़ी ने आठ में से 3.5 अंक जुटाए। गुकेश के लिए भी स्थिति काफी अलग नहीं थी लेकिन उन्होंने प्रज्ञानंद से आधा अंक अधिक हासिल किया। सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन ने चार बाजी गंवाई। ब्लिट्ज वर्ग में अब भी नौ दौर खेले जाने बाकी हैं लेकिन शीर्ष स्थान शायद पहले ही तय हो चुका है। अगर प्रज्ञानंद इस टूर्नामेंट के आखिरी दिन लय वापस पा लेते हैं तो उनके पास अब भी पोडियम पर जगह बनाने का मौका होगा।

महाभारत का हुआ था जहां युद्ध उस कुरुक्षेत्र के रहस्य

कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पाण्डवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा गया था। आओ जानते हैं कुरुक्षेत्र के 5 रहस्य। कुरुक्षेत्र भारतीय राज्य हरियाणा का एक क्षेत्र है।

छोटे भाई का वध

मान्यता अनुसार यह कहा जाता है कि भगवान श्रीकृष्ण को डर था कि भाई-भाइयों के, गुरु-शिष्यों के व संबंधी कुटुंबियों के इस युद्ध में एक दूसरे को मरते देखकर कहीं ये संधि न कर बैठें। इसलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुनने का फैसला लिया गया जहां क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हों। तब श्रीकृष्ण ने कई दूत अनेकों दिशाओं में भेजे और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने को कहा। एक दूत ने सुनाया कि कुरुक्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेंड़ टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा। उसने साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को छुरे से गोद डाला और उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस मेंड़ के पास ले गया और जहां से पानी निकल रहा था वहां उस लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। इस कहानी को सुनकर श्रीकृष्ण ने तय किया कि यही भूमि भाई-भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। जब श्रीकृष्ण आश्वस्त हो गए कि इस भूमि के संस्कार यहां पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे तब उन्होंने युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने की घोषणा की।

कुरु का क्षेत्र

दूसरी कहानी अनुसार कहते हैं कि जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे तब इन्द्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए, वह पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इन्द्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्गलोक चले गए। ऐसा अनेक बार हुआ। इन्द्र ने अन्य देवताओं को भी ये बात बताई। देवताओं ने इन्द्र से कहा कि यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इन्द्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जायेगा तो वह स्वर्ग का भागी होगा। ये बात भीष्म, कृष्ण आदि सभी जानते थे, इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया।

श्रवण कुमार की कहानी

मातृ और पितृ भक्त श्रवण कुमार की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। श्रवण कुमार जैसे पितृभक्त खोजना मुश्किल है। वे अपने अंधे माता-पिता की सेवा पूरी तत्परता से करते थे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते थे। एक बार माता-पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की और वे उन्हें कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा को चल दिए। बहुत से तीर्थ करा लेने पर एक दिन अचानक उसके मन में यह भाव आया कि पिता-माता को पैदल क्यों न चलाया जाए? उन्होंने कांवर जमीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलने को कहा। अंधे माता और पिता पैदल चलने तो लगे पर उन्होंने साथ ही यह भी कहा- बेटा इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वे तेजी से चलने लगे जब वह भूमि निकल गई तो श्रवणकुमार को माता-पिता के साथ इस तरह का व्यवहार करने पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने पैरों में गिरकर क्षमा मांगी तथा फिर से दोनों को कांवर में बिठा लिया। उनके अंधे पिता ने कहा- पुत्र इसमें तुम्हारा दोष नहीं। उस भूमि पर किसी समय मय नामक एक असुर रहता था उसने जन्मते ही अपने ही पिता-माता को मार डाला था, उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं इसीसे उस क्षेत्र में गुजरते हुए तुम्हें ऐसी बुद्धि उपजी।

कुरुक्षेत्र का महत्व

महाभारत के वनपर्व के अनुसार, कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पापमुक्त हो जाते हैं और जो ऐसा कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहीं निवास करुंगा। यहां तक कि यहां की उड़ी हुई धूल के कण पापी को परम पद देते हैं। नारद पुराण में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारागणों को कालगति से (आकाश से) नीचे गिर पड़ने का भय है, किन्तु वे, जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुनःजन्म नहीं लेते। भगवद्गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा गया है।

कुरुक्षेत्र के क्षेत्र

यहां एक विशाल तालाब है जिसका निर्माण महाभारत काल में ही हुआ था। यहां एक ज्योतिसर नामक स्थान हैं जहां पर श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। यहां पर ब्रह्मसरोवर, सन्निहित सरोवर, भद्रकाली मन्दिर, पिहोवा और श्री स्थानेश्वर महादेव मन्दिर व पूण्डरी नामक स्थान प्रसिद्ध है।

महाभारत में व्यूह रचना कितने प्रकार की थी?

महाभारत में आपने सिर्फ चक्रव्यूह का ही नाम सूना होगा। लेकिन महाभारत के युद्ध में कई प्रकार की व्यू रचना का उल्लेख मिलता है। युद्ध को लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से व्यूह रचना करता था। व्यूह रचना का अर्थ है कि किस तरह सैनिकों को सामने खड़ा किया जाए। आसमान से देखने पर यह व्यूह रचना दिखाई देती है। जैसे क्रौंच व्यूह है, तो आसमान से देखने पर क्रौंच पक्षी की तरह सैनिक खड़े हुए दिखाई देंगे। इसी तरह चक्रव्यूह को आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र के समान सैन्य रचना दिखाई देती है। आओ जानते हैं कुछ खास व्यूह रचना के बारे में।

गरुड़ व्यूह : गरुड़ पक्षी का चित्र तो देखा ही होगा आपने। यह विशालकाय पक्षी भगवान विष्णु का वाहन है। युद्ध में सैनिकों को विपक्षी सेना के सामने इस तरह पंक्तिबद्ध खड़ा किया जाता है कि जिससे आसमान से देखने पर गरुढ़ पक्षी जैसी आकृति दिखाई दे। इसे ही गरुड़ व्यूह कहते हैं। महाभारत में इस व्यूह की रचना भीष्म पितामह ने की थी।

क्रौंच व्यूह : क्रौंच सारस की एक प्रजाति है। इस व्यूह का आकार इसी पक्षी की तरह होता था। महाभारत में इस व्यूह की रचना युधिष्ठिर ने की थी।

मकरव्यूह : प्राचीन काल में मकर नाम का एक जलचर प्राणी होता है। मकर का सिर तो मगरमच्छ की तरह लेकिन उसके सिर पर बकरी के सींगों जैसे सींग होते थे, मृग और सांप जैसा शरीर, मछली या मोर जैसी पूंछ और पैंथर जैसे पैर दर्शाए भी होते थे। वैदिक साहित्य में अक्सर तिमिंगिला और मकर का साथ-साथ जिक्र होता है। लेकिन संभवतः यहां व्यूह रचना से तात्पर्य मगर से होगा मकर से नहीं। महाभारत में इस व्यूह की रचना कौरवों ने की थी। ›

कछुआ व्यूह : इसमें सेना को कछुए की तरह जमाया जाता है।

अर्धचंद्राकार व्यूह : अर्ध चंद्र का अर्थ तो आप समझते ही हैं। सैन्य रचना जब अर्ध चंद्र की तरह होती थी तो उसे अर्धचंद्राकार व्यूह रचना कहते थे। इस व्यूह की रचना अर्जुन ने कौरवों के गरुड़ व्यूह के प्रत्युत्तर में की थी।

मंडलाकार व्यूह : मंडल का अर्थ गोलाकार या चक्राकार होता है। इस व्यूह का गठन परिपत्र रूप में होता था। महाभारत में इस व्यूह की रचना भीष्म पितामह ने की थी। इसके प्रत्युत्तर में पांडवों ने व्रज व्यूह की रचना कर इसे भेद दिया था।

चक्रव्यूह : चक्रव्यूह को आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र के समान सैन्य रचना दिखाई देती है। इस चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। आपने स्पाइरल देखा होगा बस उसी तरह का यह होता है। महाभारत में इस व्यूह की रचना गुरु द्रोण ने की थी।

चक्रशकट व्यूह : महाभारत युद्ध में अभिमन्यु की निर्मम हत्या के बाद अर्जुन ने शपथ ली थी कि जयद्रथ को कल सूर्यास्त के पूर्व मार दूंगा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को बचाने के लिए इस व्यूह की रचना की थीं। लेकिन भगवान श्रीकृष्ण की चतुराई से जयद्रथ उस व्यूह से निकलकर बाहर आ गया और मारा गया।

वज्र व्यूह : वज्र एक तरह का हथियार होता है। ये दो प्रकार का होता था- कुलिश और अशानि। इसके ऊपर के तीन भाग तिरछे-टेढ़े बने होते हैं। बीच का हिस्सा पतला होता है। पर यह बड़ा वजनदार होता है। इसका आकार देखने में इन्द्रदेव के वज्र जैसा होता है। महाभारत में इस व्यूह की रचना अर्जुन ने की थी।

औरमी व्यूह : पांडवों के व्रज व्यूह के प्रत्युत्तर में भीष्म ने औरमी व्यूह की रचना की थी। इस व्यूह में पूरी सेना समुद्र के समान सजाई जाती थी। जिस प्रकार समुद्र में लहरें दिखाई देती हैं, ठीक उसी आकार में कौरव सेना ने पांडवों पर आक्रमण किया था।

श्रीन्गातका व्यूह : कौरवों के औरमी व्यूह के प्रत्युत्त में अर्जुन ने श्रीन्गातका व्यूह की रचना की थी। ये व्यूह एक भवन के समान दिखाई देता था। संभवतः इसे ही तीन शिखरों वाला व्यूह कहते होंगे। इसके अलावा सर्वतोभद्र और सुपर्ण व्यूह का उल्लेख भी मिलता है।

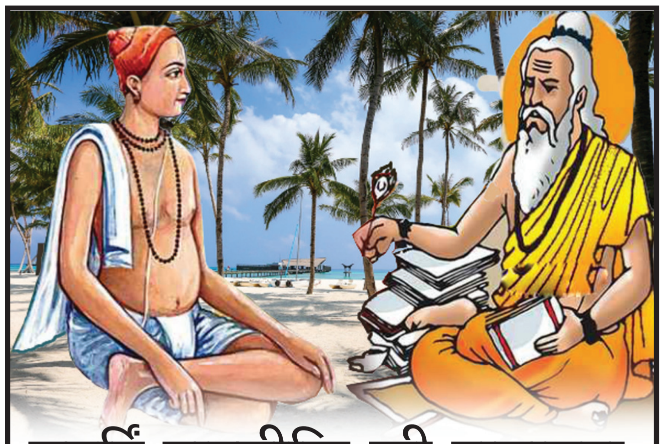

महर्षि वाल्मीकि की रामायण और गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के उत्तर कांड में फर्क क्यूं?

रामायण या रामचरित मानस के उत्तर कंाड के संबंध में बहुत लोगों को इस बात का संशय है कि इसमें घटनाओं का वर्णन वैसा नहीं है जैसा कि शोधकर्ता मानते हैं। रामायण और रामचरित मानस दोनों ही का उत्तर कांड बहुत ही भिन्न है। ऐसा क्यों? यह शोध का विषय हो सकता है। रामानंद सागर द्वारा उत्तर कंाड के नाम से उत्तर रामायण नाम का सीरियल बनाया गया है। आओ जानते हैं दोनों ही रामायण के काण्ड का फर्क।

वाल्मीकि कृत रामायण का उत्तर कांड

उत्तरकाण्ड में राम के राज्याभिषेक के अनन्तर कौशिकादि महर्षियों का आगमन, महर्षियों के द्वारा राम को रावण के पितामह, पिता तथा रावण का जन्मादि वृत्तान्त सुनाना, सुमाली तथा माल्यवान के वृत्तान्त, रावण, कुम्भकर्ण, विभीषण आदि का जन्म-वर्णन, रावणादि सभी भाइयों को ब्रह्मा से वरदान-प्राप्ति, रावण-पराक्रम-वर्णन के प्रसंग में कुबेरादि देवताओं का घर्षण, रावण सम्बन्धित अनेक कथाएँ, सीता के पूर्वजन्म रूप वेदवती का वृत्तान्त, वेदवती का रावण को शाप, सहस्त्रबाहु अर्जुन के द्वारा नर्मदा अवरोध तथा रावण का बन्धन, रावण का बालि से युद्ध और बालि की कांख में रावण का बन्धन, सीता-परित्याग, सीता का वाल्मीकि आश्रम में निवास, निमि, नहुष, ययाति के चरित, शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर वध, शंबूक वध तथा ब्राह्मण पुत्र को जीवन प्राप्ति, भार्गव चरित, वृत्रासुर वध प्रसंग, किंपुरुषोत्पत्ति कथा, राम का अश्वमेध यज्ञ, वाल्मीकि के साथ राम के पुत्र लव कुश का रामायण गाते हुए अश्वमेध यज्ञ में प्रवेश, राम की आज्ञा से वाल्मीकि के साथ आयी सीता का राम से मिलन, सीता का रसातल में प्रवेश, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के पुत्रों का पराक्रम वर्णन, दुर्वासा-राम संवाद, राम का सशरीर स्वर्गगमन, राम के भ्राताओं का स्वर्गगमन, तथा देवताओं का राम का पूजन विशेष आदि वर्णित है।

तुलसीदास गोस्वामी कृत रामचरितमानस का उत्तर कांड

इसमें मंगलाचरण, भरत विरह तथा भरत-हनुमान मिलन, अयोध्या में आनंद, श्री रामजी का स्वागत, भरत मिलाप, सबका मिलनानन्द, राम राज्याभिषेक, वेदस्तुति, शिवस्तुति, वानरों की और निषाद की विदाई, रामराज्य का वर्णन, पुत्रोत्पति, अयोध्याजी की रमणीयता, सनकादिका आगमन और संवाद, हनुमानजी के द्वारा भरतजी का प्रश्न और श्री रामजी का उपदेश, श्री रामजी का प्रजा को उपदेश (श्री रामगीता), पुरवासियों की कृतज्ञता, श्री राम-वशिष्ठ संवाद, श्री रामजी का भाइयों सहित अमराई में जाना, नारदजी का आना और स्तुति करके ब्रह्मलोक को लौट जाना, शिव-पार्वती संवाद, गरुड़ मोह, गरुड़जी का काकभुशुण्डि से रामकथा और राम महिमा सुनना, काकभुशुण्डि का अपनी पूर्व जन्म कथा और कलि महिमा कहना, गुरुजी का अपमान एवं शिवजी के शाप की बात सुनना, रुद्राष्टक, गुरुजी का शिवजी से अपराध क्षमापन, शापानुग्रह और काकभुशुण्डि की आगे की कथा, काकभुशुण्डिजी का लोमशजी के पास जाना और शाप तथा अनुग्रह पाना, ज्ञान-भक्ति-निरुपण, ज्ञान-दीपक और भक्ति की महान महिमा, गरुड़जी के सात प्रश्न तथा काकभुशुण्डि के उत्तर, भजन महिमा, रामायण माहात्म्य, तुलसी विनय और फलस्तुति और रामायणजी की आरती का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि कृत उत्तर कांड में राम के रावण वध की आगे की गाथा का वर्णन है, जिसमें राम का राज्याभिषेक, सीता परित्याग, वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश का जन्म, बचपन और सीता का जीवन। शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर का वध और इसके अलावा पूर्व के ऋषि मुनियों और राजाओं की गाथा का वर्णन मिलेगा। दूसरी ओर गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस में शिव और पार्वती का रामकथा के संबंध में संवाद, काकभुशुण्डि और गरुढ़ संवाद सहित ज्ञान और उपदेश की बातें ही ज्यादा हैं। इसमें सीता परित्याग और लव एवं कुश के बारे में उल्लेख नहीं मिलता है। विद्वान लोग मानते हैं कि ऋषि वाल्मीकि राम के समकालीन थे और गोस्वामी तुलसीदास राम के भक्त थे। यदि प्रमाण की बात सामने आए तो वाल्मीकि रामायण को ही प्रमाण मानना चाहिए, क्योंकि वही सही रामायण है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस को लिखने के पूर्व वाल्मीकि कृत रामायण सहित दक्षिण भारत की रामायण को भी पढ़ा था। अतः उन्होंने सभी को पढ़कर लिखा जबकि वाल्मीकि ने राम के जीवन को देखकर रामायण को लिखा था।

क्या कर्ण के वैवस्वत मनु यमराज और शनिदेव भाई थे?

हिन्दू पुराण और महाभारत में कई रहस्य छिपे हुए हैं। उन्हें जानना और समझने बहुत ही कठिन है। पुराणों के जानकार मानते हैं कि वैवस्वत मनु, यमराज और शनिदेव और महाभारत के कर्ण भाई भाई थे।

वैवस्वत मनु और यमराज

विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा विवस्वान् अर्थात सूर्य की पत्नी हुई। उसके गर्भ से सूर्य ने तीन संतानें उत्पन्न की। जिनमें एक कन्या और दो पुत्र थे। सबसे पहले प्रजापति श्राद्धदेव, जिन्हें वैवस्वत मनु कहते हैं, उत्पन्न हुए। तत्पश्चात यम और यमुना- ये जुड़वीं संतानें हुईं।

शनिदेव

भगवान सूर्य की तूसरी पत्नी छाया थीं। छाया को संज्ञा की छाया ही माना जाता था। छाया से ही शनिदेव का जन्म हुआ था।

कर्ण : सूर्य पुत्र कर्ण को महाभारत का एक महत्वपूर्ण योद्धा माना जाता है। कर्ण के धर्मपिता तो पांडु थे, लेकिन पालक पिता अधिरथ और पालक माता राधा थी। राजा शूरसेन की पुत्री कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वहां ऋषि दुर्वासा भी पधारे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा, 'पुत्री! मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूं जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा।' इस तरह कुंती को वह मंत्र मिल गया। एक दिन कुंती के मन में आया कि क्यों न इस मंत्र की जांच कर ली जाए। कहीं यह यूं ही तो नहीं? तब उन्होंने एकांत में बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव प्रकट हो गए। कुंती हैरान-परेशान अब क्या करें?

सूर्यदेव ने कहा, 'देवी! मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा।' इस पर कुंती ने कहा, 'हे देव! मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने मंत्र की सत्यता परखने के लिए जाप किया था।' कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, 'हे कुंती! मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र देता हूं।' इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए।

कर्ण के अन्य भाई

कुंति पुत्र कर्ण एक महान योद्ध था जो कौरवों की ओर से लड़ा था। कुंती श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ थीं। कुंति का पुत्र होने के कारण कर्ण भगवान श्री कृष्ण का भाई था। इसके अलावा पांचों पांडव भी कर्ण के भाई ही थे।

अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, खास बातें

अश्वमेध यज्ञ को कुछ विद्वान एक राजनीतिक और कुछ विद्वान इसे आध्यात्मिक प्रयोग मानते हैं। कहा जाता है कि इसे वही सम्राट कर सकता था, जिसका अधिपत्य अन्य सभी नरेश मानते थे।

कालांतर में यह यज्ञ जो नरेश जिस समाज से संबंध रखता था उस समाज की रीति के अनुसार करता था। इसके कारण इस यज्ञ को करने में कई बुरी परंपराएं भी जुड़ गई। वैदिक रीति से किया गया यज्ञ ही धर्मसम्मत माना गया है। यज्ञ का प्रारम्भ बसन्त अथवा ग्रीष्म में होता था तथा इसके पूर्व प्रारम्भिक अनुष्ठानों में प्रायः एक वर्ष का समय लगता था। इस बीच नगर में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्सव होते थे। यज्ञ करने के बाद अश्व को स्वतन्त्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। जिसके पीछे यज्ञकर्ता राजा की सेना होती थी। जब यह अश्व दिग्विजय यात्रा पर जाता था तो स्थानीय लोग इसके पुनरागमन की प्रतिक्षा करते थे। इस अश्व के चुराने या इसे रोकने वाले नरेश से युद्ध होता था। यदि यह अश्व खो जाता तो दूसरे अश्व से यह क्रिया पुनः आरम्भ की जाती थी। कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ ब्रह्म हत्या आदि पापक्षय, स्वर्ग प्राप्ति एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए भी किया जाता था। कुछ विद्वान मानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ एक आध्यात्मिक यज्ञ है जिसका संबंध गायत्री मंत्र से जुड़ा हुआ है। श्रीराम शर्मा आचार्य कहते हैं कि 'अश्व' समाज में बड़े पैमाने पर बुराइयों का प्रतीक है और 'मेधा' सभी बुराइयों और अपनी जड़ों से दोष के उन्मूलन का संकेत है। जहां भी इन अश्वमेध यज्ञ का प्रदर्शन किया गया है, उन क्षेत्रों में अपराधों और आक्रामकता की दर में कमी का अनुभव किया है। अश्वमेध यज्ञ पारिस्थितिकी संतुलन के लिए और आध्यात्मिक वातावरण की शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र से जुड़ा है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद अश्वमेध प्रायः बन्द ही हो गया।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 खूंखार शूटर मुठभेड़ में ढेर

-दिल्ली पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ ने एक संयुक्त अभियान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो खूंखार शूटरों को मुठभेड़ में मार गिराया है। मारे गए शूटरों की पहचान प्रवेश और हिमांशु के तौर पर हुई है, जो पिछले महीने हांसी में जिम चलाने वाले कपिल की हत्या में शामिल थे। पुलिस के अनुसार, ये दोनों शूटर हथियारों और गोला-बारूद से लैस थे और किसी बड़े अपराध को अंजाम देने की फिराक में थे, तभी रविवार सुबह पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई। इस गोलीबारी में एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हो गया, जबकि अन्य पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट पर कई गोलियां लगीं। एसटीएफ के एसपी विक्रांत भूषण ने बताया कि पिछले महीने हांसी में जिम चलाने वाले कपिल नाम के एक व्यक्ति की दो अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। इस घटना के संबंध में हांसी सिटी थाने में मामला दर्ज किया गया था। जांच में पता चला कि इस जघन्य अपराध को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो मुख्य शूटरों प्रवेश और हिमांशु ने अंजाम दिया था। पुलिस लगातार इनकी तलाश में थी। रविवार सुबह, काउंटर इंटेलिजेंस दिल्ली स्पेशल सेल यूनिट के इंचार्ज मंजीत को एक गुप्त सूचना मिली कि ये दोनों वांछित शूटर भारी हथियारों और गोला-बारूद से लैस हैं और एक और अपराध को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर पुलिस टीमों ने तुरंत कार्रवाई की योजना बनाई। पुलिस ने बताया कि जब पुलिस की टीमें इन दोनों शूटरों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ीं और उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। अपनी जान बचाने और जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीमों ने भी फायरिंग की। दोनों तरफ से हुई इस जबरदस्त गोलीबारी में एक पुलिस कांस्टेबल के पैर में गोली लगी, जबकि चार अन्य अधिकारियों की बुलेटप्रूफ जैकेट पर गोलियां लगीं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपराधियों ने कितनी आक्रामक तरीके से हमला किया था। इस मुठभेड़ में दोनों शूटर प्रवेश और हिमांशु भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल शूटरों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने दोनों शूटरों को मृत घोषित कर दिया। वहीं, घायल कांस्टेबल को तुरंत सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। एसपी विक्रांत भूषण ने बताया कि इस मामले में आगे की जांच की जा रही है, ताकि इस गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके नेटवर्क का पता लगाया जा सके। यह कार्रवाई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है, जो संगठित अपराध के खिलाफ उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

केदारनाथ यात्रा : भूस्खलन का खतरा, प्रशासन हाई अलर्ट पर

देहरादून (एजेंसी)। उत्तराखंड में मॉनसून की शुरुआत के साथ ही पहाड़ों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसका सीधा असर केदारनाथ यात्रा पर हो रहा है। कई क्षेत्रों से लगातार मलबा गिरने की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा एक बड़ी चिंता बनी है। रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवार ने बताया कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर कई खतरनाक इलाके चिन्हित किए हैं, जिनकी सीसीटीवी सेंटरों के माध्यम से लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। उन्होंने श्रद्धालुओं से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की पूरी तैयारी रखने और किसी भी आपातकालीन स्थिति की जानकारी तुरंत प्रशासन को देने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले चार दिनों (5 से 8 जुलाई) तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें 5 जुलाई के लिए कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट शामिल है। इसके मद्देनजर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। पुलिस, एसडीआरएफ, एनएच, पीडब्ल्यूडी और बीआरओ जैसे विभागों को भी सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर ट्रेकिंग गतिविधियों को रोकने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को चौबीसों घंटे सक्रिय रहने और किसी भी आपदा की सूचना तत्काल राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष को देने को कहा गया है। इस बीच, जुलाई की शुरुआत में सोनप्रयाग-गौरीकुंड मोटरमार्ग पर मुनकटिया के पास हुए भारी भूस्खलन के कारण यात्रा मार्ग बाधित हुआ था। हालांकि, खराब मौसम और यात्रा में अस्थायी रुकावटों के बावजूद, केदारधाम के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। प्रशासन उनकी सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

नैनीताल हादसा : बंदरों को पत्थर मारते हुए बालक खिड़की से गिरा, गंभीर घायल

नैनीताल (एजेंसी)। शहर के मल्लीताल क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक होटल में ठहरे दिल्ली के पर्यटक परिवार का तीन वर्षीय बच्चा खिड़की से 20 फीट नीचे गिरकर गंभीर रूप से चोटिल हो गया। बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, दिल्ली निवासी विशाल सोनी अपने परिवार के साथ नैनीताल घूमने आए थे और मल्लीताल स्थित एक होटल में रुके हुए थे। रविवार सुबह उनका तीन वर्षीय बेटा गौरांत कमरे में खेल रहा था। बताया गया कि इसी दौरान बालक को खिड़की के सामने कुछ बंदर दिखाई दिए, जिस पर उसने उन्हें पत्थर मारना शुरू कर दिया। इसी क्रम में अचानक उसका ध्यान हटा और वह असंतुलित होकर होटल की खिड़की से करीब 20 फीट नीचे जा गिरा। बच्चे के गिरने की आवाज सुनकर स्वजनों में चीख-पुकार मच गई। वे तत्काल गौरांत को बीडी पांडे अस्पताल ले गए। अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि बच्चे के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।

रील बनाने के चक्कर में 2 को कुचला

लुधियाना (एजेंसी)। एक युवक ने रील बनाने के चक्कर में दो महिलाओं को कुचल दिया। लुधियाना में अपनी सहेली के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद महिला बोनट पर अटक गई। थोड़ी दूर जाकर कार के सामने ही जमीन पर गिर पड़ी जिससे उसकी खोपड़ी पर पहिया चढ़ गया। महिला के शरीर की हड्डियां तक टूट गई। महिला को करीब 10 मीटर घसीटने के बाद गाड़ी सवार वहां भाग गया। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। वहीं, उसकी सहेली को भर्ती कर लिया गया। एक्सीडेंट की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट करने वाला युवक 12वीं पास है। उसे पुलिस ने अब्दुल्लापुर बस्ती से गिरफ्तार कर लिया। वहीं, उसकी कार राजस्थान से बरामद हुई।

खाड़ी से यूरोप तक, भारत बदलेगा वैश्विक समीकरण

जयशंकर का वैश्विक कूटनीतिक मिशन

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर रविवार से एक महत्वपूर्ण छह-देशीय कूटनीतिक यात्रा पर रवाना होंगे, जिसमें कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, बेल्जियम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। आज से 10 जुलाई तक चलने वाली उनकी चार खाड़ी देशों की यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण समय में हो रही है, जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद इस क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। यह यात्रा भारत के लिए इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का एक बड़ा अवसर है।

विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, जयशंकर अपनी खाड़ी यात्रा के दौरान इन देशों के नेताओं और अपने समकक्षों से मुलाकात करेंगे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक सशक्त बनाना है। इसके साथ ही, क्षेत्रीय घटनाक्रमों और आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श भी होगा, जिससे भारत की पश्चिम एशिया नीति को नई दिशा मिल सकती है।खाड़ी देशों का दौरा पूरा करने के बाद, विदेश मंत्री 13 जुलाई को न्यूयॉर्क के लिए प्रस्थान करेंगे, जहाँ वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में साल 2028-29 के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत करेंगे। यह कदम वैश्विक शासन में भारत की बढ़ती आकांक्षाओं और भूमिका को दर्शाता है, जहाँ भारत स्थायी सदस्यता के लिए भी प्रयासरत है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में, जयशंकर 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स जाएंगे। यहाँ वे तीसरी भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) की बैठक में भाग लेंगे और अपने यूरोपीय संघ तथा बेल्जियम के समकक्षों के साथ महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे। टीटीसी की शुरुआत 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों में आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से की गई थी। यह परिषद भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक तकनीकी सहयोग को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे दोनों पक्षों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास और साझाकरण में लाभ मिल सके। जयशंकर का यह बहुआयामी दौरा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक कूटनीतिक पटल पर

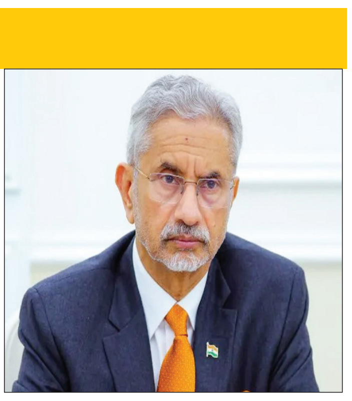

भारत की बढ़ती साख और प्रभाव को भी रेखांकित करेगा, जिससे आने वाले समय में वैश्विक समीकरणों में भारत की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है।

इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण विज्ञापन : केंद्र सरकार का मेटा को नोटिस

नई दिल्ली (एजेंसी)। (ईएमएस)।भारत सरकार ने इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े आपत्तिजनक विज्ञापनों को बढ़ावा देने के मामले में उसकी पैरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक. को नोटिस थमा दिया है। 4 जुलाई को जारी नोटिस का जवाब केंद्र सरकार ने कंपनी से सात दिनों के भीतर मांगा है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंस्टाग्राम को तत्काल प्रभाव से इसतरह के सभी विज्ञापनों को ब्लॉक करने और हटाने का निर्देश दिया है, जो बाल यौन शोषण (सीएसएएम) को बढ़ावा देते हैं या उससे संबंधित कंटेंट तक पहुँच बनाते हैं। यह कार्रवाई मीडिया रिपोर्टों के बाद की गई है, जिसमें उजागर किया गया था कि इंस्टाग्राम भारत में रेप और चाइल्ड वीडियो जैसे शब्दों का उपयोग करके पेड विज्ञापन दिखा रहा था। इन विज्ञापनों पर क्लिक करने के बाद उपयोगकर्ता टेलीग्राम चैनलों पर भेज दिए जाते थे, जहाँ कथित तौर पर बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री मात्र 99 रुपये में ब्रिकी के लिए मौजूद थी। रिपोर्ट में बताया गया कि इंस्टाग्राम पर दिखने वाले सभी विज्ञापन मेटा के मॉडरेशन सिस्टम से अनुमोदन के बाद ही दिखाते हैं, जिससे इस प्रणाली की गंभीर खामियां उजागर हुई हैं। एक मीडिया हाउस द्वारा इसतरह के एक विज्ञापन की शिकायत इंस्टाग्राम से किए जाने पर, कंपनी ने लगभग 24 घंटे बाद जवाब दिया था कि यह पोस्ट उसकी कम्यूनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं करती। हालांकि, जब मीडिया ने मेटा से मामले पर स्पष्टीकरण मांगा, तब कंपनी ने स्वीकार किया कि उसने कई विज्ञापनों को हटा दिया है, संबंधित खातों को निलंबित किया है और आपत्तिजनक यूएलआर को हटाया है। मेटा ने अपनी प्रतिक्रिया में स्वीकार किया कि कोई भी मॉडरेशन सिस्टम पूरी तरह से त्रुटिहीन नहीं होता और समीक्षा प्रक्रिया हर नियम उल्लंघन की पहचान नहीं कर पाती है।

बंगाल में 12 साल की लडक़ी की गैंगरेप के बाद हत्या

– लोगों में आक्रोश, सडक़ पर शव रखकर लगाया जाम

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में संदिग्ध हालात में 12 साल की लडक़ी की मौत से इलाके में हडक़ंप मच गया है। उसके परिवार और स्थानीय लोगों का आरोप है कि उसके साथ गैंगरेप और हत्या की गई और बाद में उसकी लाश तालाब में फेंक दी गई। इस घटना से इलाके में भारी आक्रोश है। बताया जा रहा है कि लडक़ी शनिवार शाम पास की दुकान से खाने-पीने का सामान लेने घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। परिवार ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। रविवार सुबह सूर्यपुर हाट इलाके के एक तालाब में उसकी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों का दावा है कि चार युवकों ने लडक़ी का अपहरण किया और गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद, गुस्साए लोगों ने सडक़ पर लाश रखकर विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की।

सूचना मिलने पर बारुईपुर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने एक संदिग्ध, प्रभास मंडल, को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। इस बीच, बाकी आरोपियों का पता लगाने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौत की सही वजह और रेप के आरोपों की सच्चाई का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही चल पाएगा। फिलहाल मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।

इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

घटना के बाद तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है, जबकि परिवार और स्थानीय लोग दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। पुलिस का कहना है कि घटना की गहनता से जांच की जा रही है। आरोप सिद्ध होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

राम मंदिर चंदा विवाद: विश्व हिंदू परिषद ने विपक्ष के नेताओं से मांगे सबूत

–सबूत हैं तब पुलिस को दें, अन्यथा भम्र नहीं फैलाए

अयोध्या (एजेंसी)। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने राम मंदिर निर्माण के लिए चंदे में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर विपक्षी नेताओं को खुली चुनौती दी है। उन्होंने अयोध्या के डीसीपी को पत्र लिखकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं से सबूत पेश करने की मांग की है, जिन्होंने हजारों करोड़ के घोटाले या चोरी का दावा किया है। विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार ने स्पष्ट किया कि उनके पत्र का उद्देश्य किसी पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि पुलिस से अनुरोध करना है कि वे इन बड़े, पढ़े-लिखे नेताओं से जानकारी, सबूत या गवाह जुटाएं, ताकि राम मंदिर चंदा विवाद से जुड़े आरोपों की सच्चाई सामने आ सके।

विहिप अध्यक्ष के अनुसार, सपा नेता राम गोपाल यादव ने 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का आरोप लगाया था, वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी हजारों करोड़ के चंदे की हेराफेरी की बात कहकर सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की थी। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रमुख और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और नेता संजय सिंह ने क्रमशः 200 करोड़ रुपये से अधिक की चोरी का आरोप लगाया था, जिसमें 50 कर्मचारियों के शामिल होने का दावा किया था। विहिप अध्यक्ष कुमार का कहना है कि यदि नेताओं के पास पुख्ता सबूत हैं, तब उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए, अन्यथा, बिना आधार के समाज में भ्रम फैलाने के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

कुमार के कदम पर आम आदमी पार्टी (आप) ने तीखा पलटवार किया है। आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विहिप अध्यक्ष का यह पत्र दिखाता है कि संगठन देशभर में उठ रहे चंदा चोरी के मुद्दे से बेहद परेशान और डरा हुआ है। आप नेता भारद्वाज ने आरोप लगाया कि विहिप के इरादे साफ नहीं हैं। यदि वे साफ होते, तब वे खुद अपने संगठन से जुड़े गवाह पेश करते, क्योंकि ट्रस्ट में उनके ही लोग शामिल थे। आप नेता भारद्वाज ने कहा कि विहिप नेता कुमार ने एक तरह से आत्मसमर्पण किया है, क्योंकि उनकी पार्टी या संगठन के लोग मामले में गवाह बनने को तैयार नहीं हैं।

राम मंदिर चंदे में हेराफेरी के आरोपों पर आलोक कुमार ने हर एक आरोप की बारीकी से जांच की मांग की है, यह कहकर कि चोरी, लूट या डकैती चाहे जो कहा जाए, सच केवल निष्पक्ष जांच से ही सामने आएगा। उन्होंने राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की टिप्पणियों पर कोई भी बयान देने से इंकार किया। इसके अलावा, विहिप की केंद्रीय समिति की बैठक को अयोध्या से दिल्ली शिफ्ट करने के सवाल पर कुमार ने सख्त रुख दिखाकर कहा कि यह संगठन का आंतरिक मामला है और किसी को भी इस पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है कि बैठक कहाँ आयोजित की जाए।

भारत-नेपाल सीमा पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही बंद, मधुबनी में ग्रामीणों का विरोध

मधुबनी (एजेंसी)। भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने बड़ा फैसला लिया है। मधुबनी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सीमा पर आम आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। यह व्यवस्था भारत सरकार के निर्देशों के तहत लागू की जा रही है। हालांकि, इस निर्णय का स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध जताया है। मधवापुर स्थित एसएसबी कैंप में आयोजित बैठक के बाद 48वीं बटालियन के कमांडेंट राजेंद्र कुमार ने बताया कि निर्धारित समय के दौरान केवल मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में ही सीमा पार करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि रोजमर्रा के आवश्यक सामान की आवाजाही जारी रहेगी, लेकिन भारी मात्रा में आयात-निर्यात और व्यावसायिक परिवहन पर पूरी तरह रोक रहेगी। सीमा पर बैरिकेडिंग किए जाने के बाद अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच करीब ढाई घंटे तक बैठक हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। बैठक में एसएसबी अधिकारियों के साथ बेनीपट्टी के एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, सीओ और स्थानीय थाना अध्यक्ष सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने मांग की कि शादी-विवाह, आपातकालीन परिस्थितियों और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए रात में भी सीमित आवाजाही की अनुमति दी जाए। उनका कहना था कि सीमा पूरी तरह बंद होने से बच्चों की पढ़ाई, रसोई गैस की आपूर्ति, आवश्यक सेवाओं और दोनों देशों के बीच वर्षों पुराने सामाजिक एवं पारिवारिक 'रोटी-बेटी' के रिश्तों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। बैठक बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गई। फिलहाल सीमा क्षेत्र में इस फैसले को लेकर असंतोष का माहौल है। अब सबकी नजर प्रशासन पर है कि वह सुरक्षा और स्थानीय लोगों की जरूरतों के बीच संतुलन कैसे स्थापित करता है।

प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव लड़ना फाइनल

नितिन नवीन के करीब को मिल सकता है मौका

पटना (एजेंसी)। जन सुराज पार्टी ने घोषणा की है कि उसके संस्थापक प्रशांत किशोर (पीके) पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने इस बात की पुष्टि की है। यह सीट भाजपा विधायक नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद खाली हुई है, जिससे यह चुनाव काफी अहम हुआ है।

अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि बीते चार सालों से जन सुराज ही उनकी जिंदगी है और पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरी लगन से निभाएंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बांकीपुर से मिलने वाली जीत से न केवल पार्टी का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि बिहार में एक नए राजनीतिक विकल्प की नींव भी मजबूत होगी। पीके ने कहा था कि यदि उनके चुनाव लड़ने से भाजपा बांकीपुर जैसी मजबूत सीट हारती है, तब वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बांकीपुर की जनता से पूरी ईमानदारी से काम करने का वादा किया और कहा कि अगर वे जन सुराज के प्रतिनिधि को चुनते हैं, तब वह

विधानसभा में 242 विधायकों पर भारी पड़ेगा।

इस दौरान प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने उन्हें पिछले दरवाजे से बने मुख्यमंत्री और सिलेक्टेड मुख्यमंत्री करार देकर कहा कि उनका असली चाल-चरित्र जल्द ही सामने आ जाएगा। पीके ने बांकीपुर के मतदाताओं से अपील की कि यह चुनाव केवल एक सीट जीतने का नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति को एक नया विकल्प देने और परिवर्तन की शुरुआत करने का है। उन्होंने चार लाख मतदाताओं से समर्थन मांगा।

दूसरी ओर, भाजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, नील रतन घोष (नीलू दा) का नाम करीब तय है। नील रतन घोष भाजपा के एक पुराने और भरोसेमंद कार्यकर्ता हैं, जो लंबे समय से नवीन के साथ जुड़े रहे हैं और उनके विश्वसनीय हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं की मांग पर उन्हें टिकट मिलने की संभावना है। मंदिरी के रहने वाले नीलू दा मूल रूप से पश्चिम बंगाल से हैं।

ममता की बागियों को चुनौती... तुम्हें क्या लगता है कि मैं खत्म हो गई हूं?

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में जारी बगावत के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बागी नेताओं को कड़ा संदेश दिया है। ममता ने स्पष्ट कहा कि अगर उन्हें रोकना है, तब उन्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी का चुनाव चिह्न कहीं नहीं जाने वाला और उनकी आवाज कोई नहीं दबा सकता। उन्होंने बागी नेताओं को सीधी चुनौती देकर कहा, अगर हिम्मत है, तब खुलकर भाजपा में शामिल हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं खत्म हो गई हूं? ममता ने आरोप लगाया कि ये बागी नेता अब खुले तौर पर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं और गद्दारी की भी सीमा होती है। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं ने पार्टी सिंबल पर चुनाव जीता, वहीं अब उसी पार्टी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, जिसने उन्हें राजनीतिक पहचान दी। ममता का यह

बयान तब आया है जब पार्टी के भीतर बड़ी टूट देखने को मिली है। पार्टी के 20 सांसद और 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं, जिन्होंने पार्टी सिंबल और नाम पर दावा किया है। हाल ही में, टीएमसी की पश्चिम बंगाल अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी अपने पद से इस्तीफा देकर बागी गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी के साथ नजर आईं। इन विधायकों ने 3 जून को ममता के नेतृत्व से अलग होने की घोषणा की थी, जबकि सांसदों ने 15 जून को त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी (एनसीपीआई) में विलय कर लिया था। ममता ने कहा कि वे इस बगावत का डटकर मुकाबला करेंगी और जनता के बीच अपनी पार्टी का चिह्न लेकर जाएंगी।

लालू यादव का जनता के नाम खुला पत्र: बड़ी वैचारिक लड़ाई का आह्वान

पटना (एजेंसी)। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार की राजनीति के कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के 30वें स्थापना दिवस के अवसर पर बिहार की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम एक विस्तृत खुला पत्र लिखा है। अपने इस महत्वपूर्ण संदेश में, लालू यादव ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोला है, उन पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और संविधान की मूल भावना को खतरे में डालने का गंभीर आरोप लगाया है। लालू यादव ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और देश का लोकतंत्र इस समय गंभीर चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है।

लालू यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने भाजपा पर अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल कर संस्थाओं को कमजोर करने और एक विशेष हिंदुत्व के नैरेटिव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि भाजपा ऐसा करके देश के सामने मौजूद बेरोजगारी, शिक्षा, सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों जैसे अहम मुद्दों के साथ-साथ सरकार की विफलताओं से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। आरजेडी प्रमुख ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे एक बड़ी वैचारिक लड़ाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल सत्ता हासिल करने की नहीं, बल्कि देश के मूल्यों और सिद्धांतों को बचाने की है, और इसके लिए सभी को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। लालू यादव ने जोर देकर कहा कि आरजेडी सिर्फ चुनाव लड़ने वाली एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय की स्थापना और गरीबों, वंचितों व हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ने को प्रतिबद्ध एक आंदोलन है। उन्होंने पार्टी के सफर को याद करते हुए बताया कि आरजेडी का गठन 5 जुलाई 1997 को इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया था, ताकि गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों की आवाज को बुलंद किया जा सके। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से लोगों के साथ लगातार जुड़े रहने और संसद व सड़कों पर जनहित के मुद्दों को पूरी दृढ़ता से उठाते रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी पिछले तीन दशकों से सामाजिक न्याय, समानता और समावेशी विकास के आदर्शों के प्रति अटल प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। लालू यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के अदम्य साहस, समर्पण और बलिदान की सराहना की, जिन्होंने पिछले 30 वर्षों में आरजेडी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने हर मुश्किल दौर में पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के लिए सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हार्दिक धन्यवाद किया।

संक्षिप्त समाचार

पाकिस्तान में दो महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म, चार गिरफ्तार

लाहौर , एजेंसी। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के करीबी रिश्तेदार मोहम्मद रजा डार ने अपने साथियों के साथ मिलकर दो विदेशी महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म किया है। लाहौर की एक अदालत ने शुक्रवार को मुख्य आरोपी रजा डार और उनके साथियों-हसन रजा, सिकंदर खान और साजिद अली को पांच दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि नीदरलैंड और वेनेजुएला की रहने वाली इन महिलाओं की मुलाकात अक्तूबर 2025 में सिंगापुर में रजा डार से हुई थी। रजा डार ने उन्हें पाकिस्तान बुलाया और 29 जून को लाहौर में अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया।

यूक्रेन पर हमले तेज, रूस में ईंधन का संकट नहीं : पुतिन

कीव, एजेंसी। रूसी तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के लगातार हमलों से देश में ईंधन संकट गहराने के बावजूद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस में स्थिति गंभीर नहीं है।पुतिन ने युद्धविराम के प्रस्तावों को खारिज करते हुए कहा, उनके लक्ष्य पूरे होने तक युद्ध जारी रहेगा। उन्होंने रूसी ऊर्जा क्षेत्र पर हुए हमलों को यूक्रेन की ऐसी चाल बताया है जिसका मकसद जंग में हुई क्षति से ध्यान भटकाना है। रूसी सेना ने बुधवार रात से बृहस्पतिवार सुबह तक कीव पर लगातार 11 घंटे तक बड़े पैमाने पर हमले किए, जिनमें 30 लोगों की मौत हो गई। कई नागरिक घायल हो गए। ये हमले अब तक के बड़े हमलों में से एक थे।

द. कोरिया : 2035 तक खुद के उपग्रह नेटवर्क की तैयारी

सियोल, एजेंसी। दक्षिण कोरिया ने 2035 तक खुद का उपग्रह नेटवर्क बनाने का एलान किया है। देश की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी (कासा) ने कहा, दक्षिण कोरिया सैकड़ों उपग्रहों से लैस अपना खुद का लो-अर्थ ऑर्बिट (लियो) उपग्रह संचार नेटवर्क बनाएगा। इसके साथ ही देश के पहले चंद्र मिशन के लक्ष्य को दो साल पहले यानी 2030 तक पूरा करने का फैसला किया गया है। जिंजू शहर में आयोजित एक सार्वजनिक ब्रीफिंग के दौरान कासा ने इस रणनीतिक योजना का अनावरण किया।योजना को मंजूरी मिल चुकी है।

सोशल मीडिया पाबंदी... बदलावों में देरी पर निंदा

केनबरा, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर दुनिया में अपनी तरह के पहले प्रतिबंध में प्रस्तावित बदलावों को बाधित करने वाले सांसदों की निंदा की है। उन्होंने कहा, प्रौद्योगिकी कंपनियां देरी का लाभ उठाकर ऐसे दस्तावेज नष्ट कर सकती हैं जिनका उनके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।सरकार ने इस सप्ताह संसद में संशोधन पेश किए थे, जिनका उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया की ऑनलाइन सुरक्षा निगरानी संस्था 'ई-सेफ्टी' की आयुक्त जूली इनमैन ग्रांट की शक्तियां बढ़ाना था। ये संशोधन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत विभिन्न मंचों पर 16 वर्ष से कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई बच्चों के खाते रखने पर दिसंबर से लागू प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने से संबंधित हैं। रूढ़िवादी विपक्षी लिबरल पार्टी और 'ऑस्ट्रेलियन ग्रीन्स पार्टी' ने इससे संबंधित विधेयक के मसौदे को आठ सप्ताह की सीनेट समीक्षा के लिए भेज दिया है।

लंदन में ईरानी पत्रकार पर हमले के दोषियों को जेल

लंदन, एजेंसी। लंदन की एक अदालत ने ईरानी पत्रकार पूरिया जेराती पर चाकू से हमला करने के मामले में शुक्रवार को दो रोमानियाई पुरुषों को सजा सुनाई। कोर्ट ने जॉर्ज स्टाना को 12 साल और नंदितो बादिया को 8 साल की जेल दी है। जज बॉबी चीमा-ग्रब ने कहा कि सबूतों से साफ पता चलता है कि यह हमला ईरान सरकार के इशारे पर किया गया था। मार्च 2024 में लंदन के विंबलडन इलाके में 'ईरान इंटरनेशनल' के एंकर पूरिया जेराती के पैर में चाकू मारा गया था।हमलावर वारदात के बाद हीथ्रो एयरपोर्ट से फरार हो गए थे। बाद में उन्हें रोमानिया से गिरफ्तार कर ब्रिटेन लाया गया। तीसरा संदिग्ध डेविड आंद्रेई फिलहाल रोमानिया में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहा है।

पेरू में हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की घोषणा, केइको फुजीमोरी ने दर्ज की जीत

लीमा, एजेंसी। पेरू में हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की घोषणा हो गई है। रूढ़िवादी नेता केइको फुजीमोरी ने इस कड़े मुकाबले में जीत दर्ज की है। देश की शीर्ष चुनाव संस्था ने शुक्रवार को उनकी जीत पर मुहर लगा दी। 51 साल की केइको पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरी की बेटी हैं। वह चौथी बार राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हुई थीं। चुनाव अधिकारियों के आंकड़ों के अनुसार, केइको को कुल 50.135 प्रतिशत (9,223,000) वोट मिले।

खामेनेई के जनाजे में भावुक हुए राष्ट्रपति और स्पीकर... नम आंखों से विदा करने पहुंचे लाखों लोग

तेहरान, एजेंसी। ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के जनाजे की विशाल तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार से शुरू होने वाले इस बड़े अंतिम संस्कार से पहले तेहरान में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में भावुक माहौल दिखा। समारोह के दौरान ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बघेर गालिबाफ भावुक होकर रो पड़े। इन बड़े नेताओं के साथ पूरी देश की लीडरशिप भारी भीड़ के सामने फूट-फूटकर रोती हुई नजर आई। इस विशाल और ऐतिहासिक जनाजे में बहुत ही बड़ी संख्या में देश के आम नागरिक और दुनिया के कई नेता पहुंचे हैं। ईरान की सरकार इसे केवल एक साधारण शोक समारोह नहीं बल्कि अपनी मजबूत राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक मजबूती मान रही है। इसके जरिए युद्ध के बाद देश की जनता के सामने अपनी विशाल शक्ति का बड़ा प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तेहरान की सड़कों पर बैनर लगाए गए हैं जिन पर अरबी, फारसी और अंग्रेजी में खास संदेश लिखे गए हैं।

परिजनों के ताबूत भी रखे गए : राजधानी तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला परिसर में पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनेई का राष्ट्रीय ध्वज से पूरी तरह से ढका हुआ पवित्र ताबूत भारी सम्मान के साथ रखा गया। उनके साथ उन अन्य परिजनों के ताबूत भी कतार में रखे गए जिनकी मौत युद्ध के पहले ही दिन हुए खतरनाक हवाई हमले में हुई थी। मरने वालों में उनके दामाद, बड़ी बेटी, 14 महीने की पोती और देश के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई की पत्नी शामिल थीं।

आशीर्वाद के लिए उमड़ा जनसैलाब : इस भव्य समारोह में एक बेहद भावुक दृश्य तब साफ देखने को मिला जब शोक में डूबे हजारों लोग अपने वस्त्र ताबूत से स्पर्श करवा रहे थे। इन चीजों को पवित्र ताबूत से स्पर्श कराने को ईरान में बहुत ही पवित्र और बड़े आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। बाद में खामेनेई के ताबूत को एक बड़े लाल झंडे से ढका गया जिस पर अरबी भाषा में 'या हुसैन' का नारा लिखा था।

शक्ति और एकता का कड़ा संदेश : तेहरान की सड़कों पर लगे बैनरों पर 'हमें उठ खड़ा होना होगा' जैसे संदेश लिखे गए हैं ताकि आम जनता एकजुट रहे। ताबूत पर रखा गया लाल झंडा हमेशा से अन्याय के खिलाफ कड़े संघर्ष और दुश्मनों से भारी बदले के बड़े संकल्प का एक अहम प्रतीक है। इसी बीच ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड के वरिष्ठ कमांडर जनरल अहमद वाहिदी भी कई महीनों बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए।

कई दिनों तक चलेगा शोक कार्यक्रम : शनिवार के दिन से शुरू होने वाला यह ऐतिहासिक और विशाल शोक समारोह लगातार कई दिनों तक ईरान में पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ आयोजित किया जाएगा। खामेनेई के पार्थिव शरीर को ईरान के विभिन्न बड़े शहरों के साथ-साथ पड़ोसी देश इराक के पवित्र स्थानों पर भी अंतिम दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। इस पूरी अवधि के दौरान तेहरान में सुरक्षा कारणों से कई अहम सड़कें बंद रहेंगी, हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध रहेगा और शोक कार्यक्रम आयोजित होंगे।

ईरानी नेताओं की आंख से छलके आंसू : खामेनेई को विदाई देते हुए ईरान के शीर्ष नेता अपने आंसू रोक नहीं पाए। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि उनकी अंतिम विदाई के दौरान विदेश मंत्री अब्बास अराघची और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलिबाफ फूट-फूटकर रोने लगे। तेहरान के राज्यपाल मोहम्मद सादेग मोतामदियान ने कहा कि, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

कांग्रेस पार्टी की ओर से सलमान खुर्शीद कर रहे नेतृत्व : पिछले तीन दशक से ईरान का नेतृत्व कर रहे खामेनेई की 28 फरवरी को तेहरान पर अमेरिका और इज़राइल के हवाई हमलों के पहले दिन मौत हो गई थी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साथ ही पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती और भारत से गए सिख, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्मगुरुओं ने भी दिवंगत ईरानी नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से उनकी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में पूछा गया कि खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, क्योंकि इसमें कई लोग शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा, ''जहां तक भारत सरकार का सवाल है, हमने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। हमारी ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा आज तेहरान में ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

क्या पुतिन की कुर्सी जाने वाली है ! 2026 तक क्या बदल जाएगा रूस का बॉस इस बड़े दांव से मचा हड़कंप

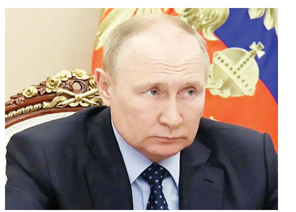

मास्को, एजेंसी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भीषण युद्ध के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अंतरराष्ट्रीय गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल, एक ऑनलाइन ट्रेडर ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भविष्य को लेकर करोड़ों रुपये की बाजी लगा दी है। यह दांव ऐसे समय में लगाया गया है जब युद्ध के लंबा खिंचने के कारण रूस के भीतर पुतिन की लोकप्रियता और उनकी पकड़ को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।

क्या सच में जा रही है पुतिन की कुर्सी : रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म 'पोलीमार्केट' पर एक यूजर ने भारी-भरकम रकम दांव पर लगाई है। 'जेडनोटलुवुईसेमेज' नाम से मौजूद इस ट्रेडर ने करीब 4.09 लाख डॉलर, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 3.89 करोड़ रुपये होते हैं। उसने इस बात का दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन दिसंबर 2026 के अंत तक रूस के राष्ट्रपति पद पर नहीं रहेंगे। यदि यह अनुमान सही साबित होता है, तो इस शख्स को करीब 25 लाख डॉलर यानी 23,80,00,000 रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया जाएगा। हैरान करने वाली बात यह है कि इस ट्रेडर की प्रोफाइल फोटो में यूक्रेन का झंडा लगा हुआ है, जो इसके राजनीतिक झुकाव की ओर इशारा करता है। प्लेटफॉर्म पर फिलहाल इस घटना के सच होने की संभावना केवल 12 प्रतिशत मानी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ट्रेडर ने इतना बड़ा जोखिम उठाया है। इतना ही नहीं, इसी ट्रेडर ने यूक्रेन द्वारा क्रीमिया पर दोबारा कब्जा करने और अगस्त के अंत तक संभावित शांति समझौते पर भी अलग-अलग रकम की बाजी लगा रखी है।

पुतिन की लोकप्रियता में गिरावट : इस दांव के पीछे की वजह रूस के भीतर बदलते समीकरण भी हो सकते हैं। हाल ही में रूस की सरकारी पोल एजेंसी ने एक सर्वे जारी किया है, जिसमें पाया गया कि 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पहली बार पुतिन की लोकप्रियता में इतनी तेज गिरावट आई है। केवल एक सप्ताह के भीतर उन पर जनता का भरोसा 3.4 प्रतिशत अंक कम हो गया है। महंगाई की बढ़ती मार, यूक्रेन के लंबी दूरी के मिसाइल हमले, ईंधन संकट और कई क्षेत्रों में इंटरनेट की पाबंदी ने आम रूसी नागरिकों के भीतर नाराजगी पैदा कर दी है। 'इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज एंड एनालिसिस ऑफ रशिया' की एक स्टडी के अनुसार, रूस में 10 में से 8 लोग चाहते हैं।

नेपाल में राष्ट्र सेवा प्रशिक्षण के लिए नए कानून की तैयारी

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल सरकार राष्ट्रीय सेवा दल से जुड़ा नया कानून लाने की तैयारी में है। इसके तहत किसी भी नेपाली नागरिक को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर प्रशिक्षित लोगों को राष्ट्र सेवा के लिए स्वयंसेवक के रूप में तैनात किया जा सकेगा। रक्षा मंत्री का कार्यभार भी संभाल रहे प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह (बालेन) ने यह विधेयक संघीय संसद सचिवालय में पंजीकृत कराया है।

इस विधेयक के उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि विद्यार्थियों में देशभक्ति, जनसेवा और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित की जाएगी। उन्हें नैतिक, अनुशासित और जिम्मेदार नागरिक बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। विधेयक में कहा गया है कि राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुसार किसी भी नेपाली नागरिक को प्रशिक्षण देकर राष्ट्र सेवा के लिए तैयार किया जा सकेगा। इसमें नेतृत्व क्षमता बढ़ाने और विकास व निर्माण कार्यों के लिए स्वयंसेवकों का समूह तैयार करने का भी प्रावधान है।

सेवा दल के प्रमुख संरक्षक होंगे प्रधानमंत्री : प्रस्ताव के अनुसार प्रधानमंत्री सेवा दल के प्रमुख संरक्षक और रक्षा मंत्री संरक्षक होंगे। नेपाल सरकार, प्रधान सेनापति की सिफारिश पर अवकाश प्राप्त उपरथियों में से एक को दो वर्ष के लिए कार्यकारी महानिदेशक नियुक्त करेगी। विधेयक में कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों, युद्ध या आंतरिक संघर्ष के समय किसी भी नेपाली नागरिक को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

प्रशिक्षण पूरा करने वाले विद्यार्थियों और अन्य नागरिकों को मंत्रिपरिषद के तय नियमों के अनुसार राष्ट्र सेवा में लगाया जा सकेगा। कक्षा 8 से 10 तक के विद्यार्थियों को जूनियर और कक्षा 11-12 के विद्यार्थियों को सीनियर डिवीजन में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए आवश्यक प्रशिक्षक नेपाली सेना उपलब्ध कराएगी।

एम्पायर स्टेट पर प्रपोज करने वाले रूसी कपल एंजेला और इवान को पुलिस ने किया है गिरफ्तार

वाशिंगटन, एजेंसी। 1 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क की 1,454 फीट (करीब 443 मीटर) ऊंची एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना घटी है। रूस के रहने वाले मशहूर रूफटॉपर्स एंजेला निकोलाउ और इवान बीरकुस ने बिना किसी सुरक्षा उपकरण के इस गगनचुंबी इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंचकर सगाई कर ली। 32 वर्षीय इवान ने 33 वर्षीय एंजेला को 103वीं मंजिल के स्पायर पर 443 मीटर की ऊंचाई पर शादी के लिए प्रपोज किया। दोनों ने वहां एक बड़ा बैनर भी फहराया जिस पर प्यार और शांति का एक खास संदेश बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था।

इस बड़े और जोखिम भरे स्टंट के वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं और पूरी दुनिया में इसकी भारी चर्चा हो रही है। लेकिन जैसे ही यह कपल अपना हैरतअंगेज कारनामा पूरा करके वहां से नीचे उतरा, वैसे ही न्यूयॉर्क पुलिस ने उन दोनों को तुरंत अपनी हिरासत में ले लिया।

पुलिस ने बताया कि ये दोनों बिना किसी आधिकारिक अनुमति के इमारत के अत्यंत प्रतिबंधित और सुरक्षित हिस्से में गैर-कानूनी तरीके से पूरी तरह घुस गए थे। उन पर आपराधिक अतिक्रमण, लापरवाही से दूसरों की जान खतरे में डालने और गंभीर चोरी जैसे बेहद सख्त आरोप भी लगाए गए हैं।

एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का प्रबंधन : बिल्डिंग के प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि इस पूरी घटना के दौरान वहां मौजूद पर्यटकों या किसी भी कर्मचारी को कोई सीधा खतरा बिल्कुल भी नहीं हुआ। प्रबंधन ने यह भी साफ कहा कि अगर कोई अपने शादी के प्रस्ताव को यादगार बनाना चाहता है तो इसके लिए ऑब्जर्वेशन डेक पहले से मौजूद है। ऐसे जानलेवा और अत्यंत खतरनाक तरीके अपनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इससे किसी भी वक्त कोई बड़ा और गंभीर हादसा हो सकता है।

दुनिया के मशहूर रूफटॉपर्स का इतिहास : यह कोई पहला मौका नहीं है जब एंजेला और इवान ने इतनी ऊंची इमारत पर अपना यह खतरनाक और हैरान करने वाला कारनामा दुनिया को दिखाया हो। ये दोनों पहले भी मलेशिया की दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत मर्डेका 118 और चीन की गोल्डिन फाइनैंस 117 जैसी इमारतों पर सफलतापूर्वक चढ़ चुके हैं। इन दोनों की इसी बेहद खतरनाक और रोमांचक जिंदगी पर साल 2024 में नेटफ्लिक्स ने 'स्काईवॉकर्सः ए लव स्टोरी' नाम की चर्चित डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। इवान का मानना है कि रूफटॉपिंग उन्हें जीने की बड़ी प्रेरणा देती है, वहीं एंजेला भी इस खतरनाक काम को अपनी एक खास कला मानती हैं। ये दोनों खुद यह बात स्वीकार कर चुके हैं कि उन्हें पहले भी कई अन्य देशों में ऐसे खतरनाक स्टंट के दौरान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। एंजेला का कहना है कि जब बाकी लोग नियमों का पालन करते हैं, तब वे सिस्टम से सचमुच बहुत ऊपर जाकर असली रोमांच का बड़ा एहसास करते हैं। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से तक पहुंचने का ऐसा कारनामा पहले बहुत ही कम लोगों ने किया है, जिनमें 1994 में फ्रांस के पर्वतारोही एलेन रॉबर्ट शामिल थे।

इराक में भ्रष्टाचार पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' ! आधी रात 'ग्रीन जोन' में घुसी फोर्स, सांसद-मंत्री समेत 47 गिरफ्तार

बगदाद , एजेंसी। इराक की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब राजधानी बगदाद के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले 'ग्रीन जोन' में रविवार तड़के भारी सुरक्षा बलों ने छापेमारी शुरू की। प्रधानमंत्री अली अल जैदी के सीधे आदेश पर शुरू किए गए इस महाभियान के तहत अब तक 47 प्रभावशाली नेताओं और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस कार्रवाई को इराक के इतिहास में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक का सबसे कड़ा प्रहार माना जा रहा है। एलीट काउंटर टेररिज्म सर्विस ने संभाली कमान न्यूज एजेंसी रॉयटर्स और स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस ऑपरेशन को इराक की एलीट काउंटर टेररिज्म सर्विस ने अंजाम दिया। सुरक्षा बलों ने रविवार तड़के उन ठिकानों पर दबिश दी, जिन्हें सत्ता का केंद्र माना जाता है।

सरकारी समाचार एजेंसी आईएनए ने बताया कि पकड़े गए लोगों में कई वर्तमान सांसद और हाई-प्रोफाइल नौकरशाह शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक, यह पूरी कार्रवाई अदालत द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट के आधार पर की गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि सरकार ने इसके लिए पुख्ता कानूनी तैयारी की थी।

प्रधानमंत्री का 'भ्रष्टाचार मुक्त इराक' मिशन : इसी साल मई में सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने पद की शपथ लेते ही जनता से वादा किया था कि वे सरकारी खजाने को लूटने वालों को नहीं छोड़ेंगे। सरकार के प्रवक्ता हैदर अल अबूदी ने मीडिया को बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी संस्थानों को मजबूत करना और सार्वजनिक धन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री जैदी खुद इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव को टाला जा सके। इस भ्रष्टाचार नेटवर्क का खुलासा तब हुआ जब रिफाइनिंग मामलों के उप तेल मंत्री अदनान अल जुमैली को हिरासत में लिया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक, अल जुमैली की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में कई चौंकाने वाले नाम सामने आए। उन्हीं के बयानों और मिले दस्तावेजों के आधार पर सुरक्षा बलों ने अन्य 46 अधिकारियों पर शिकंजा कसा है। हालांकि, रिपोर्टों में यह भी संकेत दिया गया है कि कुछ संदिग्ध अधिकारी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में छापेमारी जारी है। इराक सरकार का कहना है कि यह केवल शुरुआत है और भ्रष्टाचार के इस विशाल नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। इस कार्रवाई ने न केवल इराक, बल्कि पूरे खाड़ी देशों में चर्चा छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रधानमंत्री अली अल जैदी अपने इस अभियान में सफल रहते हैं, तो इससे इराक की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है और विदेशी निवेशकों का भरोसा भी बहाल होगा।

ब्रिटेन के कैम्ब्रिजशायर में मंदिर के लिए नहीं दी जमीन, चर्च और मुस्लिम ग्रुप को सौंप दी; त्योहार नहीं मना पाते हिंदू

नॉर्थस्टोव, एजेंसी। ब्रिटेन के कैम्ब्रिजशायर स्थित नए शहर नॉर्थस्टोव में अपना पहला पूजा स्थल बनाने की कोशिश कर रहे ब्रिटिश हिंदुओं को तगड़ा झटका लगा है। स्थानीय काउंसिल ने एक जमीन के टुकड़े को हिंदू चैरिटी को देने के बजाय एक चर्च और मुस्लिम ग्रुप को आवंटित कर दिया है। यह फैसला सामने आने के बाद इलाके में रहने वाले करीब 150 हिंदू परिवारों में काफी निराशा है।

क्या है पूरा मामला : साउथ कैम्ब्रिजशायर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने 0.25 हेक्टेयर जमीन को 999 साल के लिए 'नॉर्थस्टोव चर्च नेटवर्क' को लीज पर दे दिया है। इसके लिए उन्हें सिर्फ नाममात्र का किराया चुकाना होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय निवासियों द्वारा बनाए गए 'हिंदू समाज नॉर्थस्टोव' ने भी इस जमीन के लिए बोली लगाई थी। उन्होंने यहां एक मंदिर के साथ-साथ 'सर्वधर्म' और वेलबीइंग सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, बोलियों का आकलन करने वाले काउंसिल के अधिकारियों ने एचएसएन के प्रस्ताव को 65% और एनसीएन के प्रस्ताव को 81% अंक दिए, जिसके कारण जमीन चर्च नेटवर्क को मिल गई।

मुस्लिम ग्रुप कैसे बना हिस्सेदार : नॉर्थस्टोव चर्च नेटवर्क के प्रस्ताव में नॉर्थस्टोव के मुसलमानों को मुख्य किरायेदार (एंकर टेनेंट) के रूप में शामिल किया गया था। इस प्रस्ताव में उनके लिए एक अलग इस्लामिक प्रार्थना कक्ष और शिक्षा केंद्र बनाने की बात शामिल है। नॉर्थस्टोव मुस्लिम ग्रुप के अध्यक्ष नवाश ने बताया कि शहर में लगभग 200 मुस्लिम हैं, जिन्हें दिन में पांच बार नमाज पढ़ने के लिए एक स्थायी जगह की जरूरत थी, क्योंकि कम्युनिटी स्पेस इतने लंबे समय तक खुले नहीं रहते। यही वजह है कि उन्होंने एंकर टेनेंट के तौर पर आवेदन किया था। वहीं, एनसीएन के प्रवक्ता का कहना है कि स्थानीय समुदायों और आस्था समूहों को भी जगह किराए पर लेने की अनुमति दी जाएगी। कैम्ब्रिजशायर में कई चर्च और मस्जिदें हैं, लेकिन एक भी हिंदू मंदिर नहीं है। हिंदुओं को पूजा करने के लिए दो घंटे का सफर तय करके बर्मिंघम या वेम्बली जाना पड़ता है। वे रात भर के लिए कम्युनिटी स्पेस किराए पर नहीं ले सकते, जिससे गणपति जैसे त्योहार मनाना मुश्किल हो जाता है। हालात ये हैं कि भगवान की मूर्तियों को कैरी बैग में रखकर गैराज में रखना पड़ता है। जगह-जगह ले जाने के कारण कई मूर्तियां खंडित भी हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से यूके गए अभिषेक श्रीवास्तव कहते हैं कि उन्हें कभी-कभी लगता है कि यूके आकर उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि उनके 9 और 12 साल के बच्चे हिंदू त्योहारों में हिस्सा नहीं ले पाते। वहीं, 16 साल की इवा का कहना है कि उसने कभी रात भर शिवरात्रि नहीं मनाई और न ही कभी 'हवन' देखा है।

बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहा, 'एक ही मकसद...बलूचिस्तान की आजादी'

इस्लामाबाद, एजेंसी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ग्वादर में जिवानी के पनवान इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर हुए जानलेवा फिदायीन हमले (सुसाइड कमांडो) की जिम्मेदारी ली है. द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, अलगाववादी समूह ने दावा किया है कि हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के जवान और दर्जनों घायल हो गए. रिपोर्ट के मुताबिक, यह खतरनाक ऑपरेशन शुक्रवार शाम को बीएलए की एलीट मजीद ब्रिगेड ने किया था. समूह ने बताया कि एक सुसाइड बॉम्बर, जिसकी पहचान अताउल्लाह बलूच उर्फ अजमल के तौर पर हुई है, ने स्थानीय समय के मुताबिक शाम करीब 6:32 बजे विस्फोटकों से लदे माजदा ट्रक को मजबूत कोस्ट गार्ड कैंप में घुसा दिया. इस दौरान एक बड़ा धमाका हुआ. एक आधिकारिक बयान में, बीएलए के प्रवक्ता जीयंद बलूच ने कहा कि, इस जबरदस्त धमाके की वजह से, कोस्ट गार्ड्स का मजबूत कॉलोनियल कैंप पूरी तरह से मलबे के ढेर में बदल गया. बीएलए की मीडिया विंग, हक्कल ने 43 सेकंड का एक वीडियो क्लिप जारी किया, जिसमें कथित तौर पर एक खतरनाक धमाके से कुछ देर पहले विस्फोटकों से भरा ट्रक कैंप कंपाउंड में घुसता हुआ दिखाया गया है. चैनल द्वारा शेयर किए गए बाद के फुटेज से पता चला कि मिलिट्री कैंप का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से जमींदोज (तबाह) हो गया था. ग्रुप ने कहा कि शुरुआती गाड़ी पर बमबारी के तुरंत बाद उसके टैक्टिकल विंग, फतेह स्क्वाड ने मिलकर जमीन पर हमला किया. बीएलए के बयान में कहा गया कि, हमले के तुरंत बाद, उनके संगठन की आगे की यूनिट, फतेह स्क्वाड, तेजी से और संगठित तरीके से आगे बढ़ी, और तबाह हुए कैंप पर चारों तरफ से हमला किया. बागियों ने दावा किया कि फतेह स्क्वाड के लड़ाकों ने बचे हुए कोस्ट गार्ड के लोगों से बहुत करीब से मुकाबला किया. उन्होंने कहा कि संयुक्त ऑपरेशन के दौरान 30 से ज्यादा लोग मारे गए. बीएलए प्रवक्ता ने कहा कि, घायलों और मलबे में फंसे लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए, दुश्मन के मारे जाने की संख्या में और बढ़ोतरी होने की बहुत ज्यादा संभावना है. बीएलए ने कहा कि वह जल्द ही अपने आधिकारिक चैनलों के जरिए ऑपरेशन की पूरी जानकारी जारी करेगा. बैन किए गए संगठन ने आगे कहा कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को टारगेट करने वाला उसका हथियारबंद कैंपेन तब तक उसी तेजी से जारी रहेगा जब तक कि बलूचिस्तान की पूरी आजादी का उसका आखिरी मकसद हासिल नहीं हो जाता. पाकिस्तानी मिलिट्री और सरकारी अधिकारियों ने अभी तक जिवानी हमले में मृतकों और घायलों की सही संख्या या हुए नुकसान की हद को पुष्टि करने वाला कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

मजीद ब्रिगेड का आत्मघाती धमाका : जानकारी के मुताबिक, यह हमला ग्वादर के जिवानी इलाके के पनवान में स्थित पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के कैंप पर हुआ। हमले की जिम्मेदारी बीएलए की सबसे खतरनाक विंग 'मजीद ब्रिगेड' ने ली है। रिपोर्ट के अनुसार, अताउल्लाह बलूच उर्फ अजमल नाम के एक आत्मघाती हमलावर ने शुक्रवार की शाम करीब 6:32 बजे विस्फोटकों से लदे एक भारी ट्रक को सीधे कोस्ट गार्ड के कैंप के भीतर घुसा दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि कैंप की मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं और पूरा इलाका मलबे के ढेर में बदल गया। हैरानी की बात यह है कि बीएलए यहीं नहीं रुकी। आत्मघाती ट्रक बम धमाके के तुरंत बाद संगठन के 'फतेह स्क्वाड' ने जमीनी स्तर पर मोर्चा संभाल लिया।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सूरत नगर निगम की समन्वय बैठक में भारी हंगामा

अवैध निर्माण पर विधायक कुमार कानाणी का वॉकआउट, अधिकारियों पर बरसे जनप्रतिनिधि

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत नगर निगम में विधायकों के साथ आयोजित मासिक समन्वय बैठक इस बार बेहद हंगामेदार रही। सामान्यत: शांतिपूर्ण रहने वाली इस बैठक में सत्तारूढ़ दल के जनप्रतिनिधियों ने ही अधिकारियों की कार्यप्रणाली और निष्क्रियता पर तीखा विरोध जताया।

अवैध निर्माण, बारिश के बाद खराब हुई सड़कों और हालिया विवादित नासीरनगर ध्वस्तीकरण अभियान को लेकर बैठक में तीखी बहस हुई। वराछा के विधायक कुमार कानाणी ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार (वॉकआउट) कर दिया।

बैठक में एक सांसद और आठ विधायक उपस्थित थे। शुरुआत से ही जनप्रतिनिधियों ने जनता की समस्याओं को लेकर प्रशासन को घेरा।

कुमार कानाणी ने कहा कि वराछा सहित पूरे सूरत में अवैध निर्माण तेजी से बढ़ रहे हैं। रिहायशी क्षेत्रों में बिना अनुमति के व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, जिससे ट्रैफिक और पार्किंग की गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे।

उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार लिखित और मौखिक शिकायतों के बावजूद अधिकारी कोई कदम नहीं उठाते और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो वे नगर निगम कार्यालय के बाहर अनशन करेंगे। इसके बाद वे बैठक छोड़कर बाहर चले गए।

स्थिति बिगड़ती देख डिप्टी कमिश्नर सहित वरिष्ठ अधिकारी उन्हें मनाने पहुंचे। लगभग 15 मिनट तक चली बातचीत के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद कानाणी दोबारा बैठक में शामिल हुए।

इसके बाद भी उन्होंने छोटे वराछा गांव की सरकारी जमीन पर कथित रूप से बनी 'बांग्लादेश कॉलोनी' नामक अवैध बस्ती को हटाने तथा सनिया हेमाद क्षेत्र के कृष्णा पार्क इंडस्ट्रियल और कॉटेज इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में हुए अवैध निर्माणों पर तत्काल बुलडोजर चलाने की मांग की।

नासीरनगर ध्वस्तीकरण पर भी प्रशासन घिरा

बैठक में नासीरनगर ध्वस्तीकरण का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठा। कुमार कानाणी ने नगर आयुक्त से सवाल किया कि इतने बड़े ध्वस्तीकरण अभियान की जानकारी आयुक्त को पहले से नहीं थी, यह बात स्वीकार्य नहीं है।

पूर्व मंत्री एवं विधायक विनु मोरड़िया ने भी इस मुद्दे पर प्रशासन को घेरा। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से अनेक गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार बेघर हो गए हैं। केवल छोटे अधिकारियों को निलंबित कर देने से जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती। उन्होंने पूछा कि इस पूरे मामले के बड़े जिम्मेदार अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई।

सड़कों और उद्यानों की बदहाल स्थिति पर भी सवाल

विधायक संदीप देसाई ने वार्ड 10, 29 और 30 की जर्जर सड़कों के फोटो नगर आयुक्त को दिखाते हुए कहा कि ड्रेनेज-रोड प्रोजेक्ट पूरा होने के तुरंत बाद ही सड़कें धंस गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि इंजीनियर कभी साइट पर नहीं जाते, जिससे ठेकेदार घटिया गुणवत्ता का काम कर करोड़ों रुपये के बिल पास करा लेते हैं।

उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और उद्यानों के रखरखाव के लिए आगामी बजट में 10 से 15 करोड़ रुपये का अलग प्रावधान करने की मांग की।

लिंबायत की विधायक संगीता पाटिल ने अपने क्षेत्र की टूटी सड़कों की तत्काल मरम्मत की मांग की।

सांसद प्रभु वसावा ने कहा कि जिन ठेकेदारों ने गारंटी अवधि के दौरान भी खराब सड़कें बनाई हैं, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने पूर्णा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए पीने के पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी उठाया।

नगर आयुक्त का आश्वासन

सभी जनप्रतिनिधियों की शिकायतें सुनने के बाद नगर आयुक्त ने कहा कि उठाए गए सभी मुद्दे गंभीर हैं। अवैध निर्माणों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाई जाएगी तथा खराब सड़कों के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों और संबंधित इंजीनियरों की जांच कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सूरत में रिहायशी मकान में चल रहे जुआघर पर छापा, 7 महिलाएं गिरफ्तार, एक लाख से अधिक का सामान जब्त

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

UTRAN POLICE STATION SURAT CITY
ઉત્રાણ પોલીસ સ્ટેશન સુરત શહેર

सूरत शहर में अवैध जुआ गतिविधियों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में उत्राण पुलिस ने उमरागाम क्षेत्र स्थित एक रिहायशी मकान पर छापा मारकर जुआ खेल रही सात महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है।

पुलिस को सूचना मिली थी कि उमरागाम स्थित राधे रेजीडेंसी के एक मकान में महिलाएं जुआ खेल रही हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से छापा मारा और मौके से सात महिलाओं को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने मौके से नकद राशि, मोबाइल फोन और जुआ खेलने में इस्तेमाल होने वाला अन्य सामान सहित एक लाख रुपये से अधिक का मुद्दामाल जब्त किया है। सभी सामान को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

उत्राण पुलिस ने संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि यह जुआघर कब से संचालित हो रहा था तथा इसमें अन्य लोगों की भी संलिप्तता है या नहीं।

पुलिस का कहना है कि शहर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रांदेर ज़ोन बिल्डर के सामने नतमस्तक

सूरत नगर निगम की ही जमीन पर अतिक्रमण, नया रोड खोदकर वर्षा जल लाइन में अवैध कनेक्शन

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत नगर निगम के रांदेर ज़ोन अंतर्गत पाल GEB कार्यालय के सामने स्थित आरक्षित (रिजर्व) प्लॉट पर एक बिल्डर द्वारा कथित रूप से अतिक्रमण कर मजदूरों के लिए झोपड़ियां बना दी गई हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में बनाए गए नए कार्पेट रोड को खोदकर वर्षा जल निकासी (स्टॉर्म वॉटर) लाइन में अवैध कनेक्शन भी जोड़ दिया गया है।

भाजपा की पूर्व पार्षद उषा पटेल ने इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से अधिकारियों पर बिल्डर के पक्ष में काम करने के आरोप लग रहे हैं।

आरोप है कि नगर निगम आम नागरिकों के छोटे-छोटे अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाने में तत्पर रहता है, लेकिन अपनी ही जमीन पर हुए कब्जे और सरकारी सड़क को नुकसान पहुंचाने के मामले में चुप्पी साधे हुए है।

उषा पटेल ने शिकायत में बताया कि पाल क्षेत्र में नगर निगम के आरक्षित प्लॉट पर बिल्डर ने मजदूरों के लिए झोपड़ियां बना दी हैं। साथ ही, रविवार की छुट्टी का फायदा उठाकर नए बने कार्पेट रोड की खुदाई कर मुख्य वर्षा जल लाइन के मैनहोल में अवैध कनेक्शन भी जोड़ दिया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि जीपीएस लोकेशन सहित फोटोग्राफिक सबूत देने के बावजूद नगर निगम ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। नगर निगम की अपनी जमीन पर अतिक्रमण, सार्वजनिक धन से बनी सड़क को नुकसान और वर्षा जल निकासी व्यवस्था में अवैध हस्तक्षेप के बावजूद प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है।

पूर्व पार्षद ने मांग की है कि मामले की तत्काल स्थल जांच कराई जाए, नगर निगम की जमीन से अतिक्रमण हटाया जाए, जिम्मेदार बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए तथा सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई भी उससे वसूली जाए। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से रांदेर ज़ोन के अधिकारियों पर बिल्डर को संरक्षण देने के आरोप लगाए जा रहे हैं।

---

315 वां आरटीआई और कानूनी वेबिनार

लोकतांत्रिक जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करने पर विशेष चर्चा

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

Aatmdeep
Suresh Maurya Surat Gujarat
जानकारियां, सार्वजनिक करने का
खुद खुद सार्वजनिक करने.
zoom

हाल ही में 'आरटीआई और लोकतांत्रिक जवाबदेही' (RTI & Democratic Accountability) विषय पर 315वें आरटीआई एवं कानूनी वेबिनार का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य वक्ता आरटीआई रिसोर्स पर्सन वीरेंद्रकुमार ठक्कर, मध्य प्रदेश के पूर्व राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह एवं आत्मदीप सहित कई कानूनी विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वेबिनार में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के संवैधानिक महत्व, इसके प्रभावी कार्यान्वयन और जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई।

नीचे इस वेबिनार से जुड़ी मुख्य बातें और विभिन्न मामलों में दिए गए कानूनी परामर्श की विस्तृत रिपोर्ट दी गई है:

1. आरटीआई का संवैधानिक आधार और विकास

मुख्य वक्ता वीरेंद्रकुमार ठक्कर ने स्पष्ट किया कि आरटीआई केवल एक वैधानिक कानून नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में निहित है।

उन्होंने इसके विकासक्रम को रेखांकित करते हुए बताया कि कैसे 1996 के जन आंदोलनों (जैसे राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन की जनसुनवाई) से होते हुए अक्टूबर 2005 में यह एक राष्ट्रव्यापी सशक्त कानून बना। आरटीआई मुख्य रूप से तीन स्तंभों पर काम करता है:

सक्रिय प्रकटीकरण (धारा 4): सरकारी विभागों द्वारा स्वत: जानकारी सार्वजनिक करना।

मांग पर पहुंच: नागरिकों द्वारा आवेदन करने पर 30 दिनों के भीतर सूचना देना।

प्रवर्तन तंत्र: सूचना न देने पर अपील प्रक्रिया और लोक सूचना अधिकारियों (PIO) पर दंड का प्रावधान।

2. आरटीआई कार्यान्वयन में मुख्य चुनौतियां

वेबिनार में देश भर में आरटीआई के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई:

सूचना आयोगों में बैकलॉग: अदालतों और आयोगों में लंबित मामलों और आयुक्तों के खाली पदों के कारण फैसलों में देरी हो रही है।

कार्यकर्ताओं की सुरक्षा: उत्तराखंड जैसे राज्यों का हवाला देते हुए आरटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ बढ़ती धमकियों और हिंसा पर चिंता जताई गई।

गोपनीयता बनाम जनहित: आरटीआई अधिनियम की धारा 8 के तहत दी गई छूट और नए डेटा संरक्षण कानूनों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, ताकि व्यक्तिगत गोपनीयता की आड़ में महत्वपूर्ण जनहित की सूचनाओं को दबाया न जा सके।

प्रशासनिक शिथिलता: गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों में जन सूचना अधिकारियों द्वारा जानकारी देने में की जा रही देरी और मनमाने आदेशों की आलोचना की गई।

3. नए श्रम कानूनों और ईपीएफ (EPF) पर चर्चा

वेबिनार में 21 नवंबर, 2025 से लागू हुए नए श्रम संहिताओं (Labour Codes) पर भी चर्चा हुई। वीरेंद्रकुमार ठक्कर ने बताया कि इन सुधारों ने 29 पुराने कानूनों को समाहित कर लिया है, जिससे इसका दायरा 18 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ कामगारों (जिसमें प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी शामिल हैं) तक पहुंच गया है। कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि (PF) कटौती की 1800 रुपये की नई सीमा पर जताई गई चिंताओं पर उन्होंने सलाह दी कि किसी भी प्रकार के उल्लंघन के खिलाफ श्रम अदालतों और आरटीआई के माध्यम से कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।

विभिन्न मामलों में विशेषज्ञों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश (Action Items)

बैठक के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों से जुड़े कानूनी और प्रशासनिक मामलों पर विशेषज्ञों ने निम्नलिखित रणनीतिक सुझाव दिए:

छत्तीसगढ़ पर्यावरण मामला: छत्तीसगढ़ पर्यावरण विभाग को व्यापक जानकारी मांगने के बजाय केंद्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB/SPCB) की विशिष्ट और मौजूदा रिपोर्टों पर केंद्रित आरटीआई आवेदन दोबारा तैयार करने की सलाह दी गई।

राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत: सेवा मामलों में महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में शिकायत दर्ज कराने और यह स्पष्ट घोषणा करने को कहा गया कि यह मामला किसी अन्य अदालत में लंबित नहीं है।

बिजली चोरी और जुर्माना मामला: बिजली विभाग में मीटरिंग की समस्या के बावजूद चोरी का जुर्माना लगाने के खिलाफ नियमानुसार 50' राशि जमा कर अधीक्षण अभियंता (Superintending Engineer) के समक्ष अपील दायर करने का निर्देश दिया गया।

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का नियम: यूपी के उस नियम को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का सुझाव दिया गया जो आयोग को अपने ही फैसलों पर पुनर्विचार (Review) की अनुमति देता है, क्योंकि यह मूल आरटीआई अधिनियम की भावना के विपरीत हो सकता है। इसके अलावा, झूठे हलफनामों के मामले में आरटीआई के जरिए तारीखें साबित कर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई।

सीएम हेल्पलाइन शिकायत: शिकायत को बिना उचित समाधान के बंद करने के कारणों को जानने के लिए संबंधित विभाग में नया आरटीआई आवेदन दायर करने की सलाह दी गई।

प्रथम अपील में देरी: प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा समय पर निर्णय न लेने के खिलाफ राज्य सूचना आयोग (SIC) में दूसरी अपील करने तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ सामान्य प्रशासन विभाग में शिकायत दर्ज कराने की रणनीति सुझाई गई।

महाराष्ट्र सरकार के नियमों को चुनौती: आरटीआई के संबंध में महाराष्ट्र सरकार के कुछ नियमों को 'अल्ट्रा वायर्स' (मूल कानून के दायरे से बाहर) होने के आधार पर उच्च न्यायालय में चुनौती देने का परामर्श दिया गया।

पारिवारिक पेंशन मामला: बच्चे की आजीविका से जुड़े इस संवेदनशील मामले में त्वरित समाधान के लिए संबंधित सूचना आयुक्त से व्यक्तिगत मुलाकात कर अनुरोध करने की सलाह दी गई।

पर्यावरणीय उल्लंघन: नदी के पास औद्योगिक गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ उचित दस्तावेजों के साथ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में 'पत्र याचिका' (Letter Petition) दायर करने का सुझाव दिया गया।

निष्कर्ष और आगे की राह

विशेषज्ञ आत्मदीप ने सत्र का समापन करते हुए प्रतिभागियों को सलाह दी कि वे केवल शिकायतें दर्ज कराने के बजाय 'अपील मार्ग' का अधिक उपयोग करें, क्योंकि अपीलीय प्राधिकारियों के पास व्यापक अधिकार क्षेत्र होता है और वे जुर्माना भी लगा सकते हैं। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया कि आरटीआई को सूचना प्राप्त करने का एकमात्र जरिया न मानकर अन्य वैकल्पिक कानूनी रास्तों का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

सभी प्रतिभागियों ने इस बात पर सहमति जताई कि लोकतंत्र को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए भविष्य में ऐसे आरटीआई चर्चा कार्यक्रमों में आम जनता की भागीदारी को बड़े पैमाने पर बढ़ाना अनिवार्य है।